वर्ष-02 अंक-05 अप्रैल-2024 | ₹ 20/-

RNI No. UPHIN/2022/84386

लखनऊ जंक्शन

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

SACTEM का संकल्प...

अब हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक से नही होगी कोई मौत!

When every second counts, we're there first!

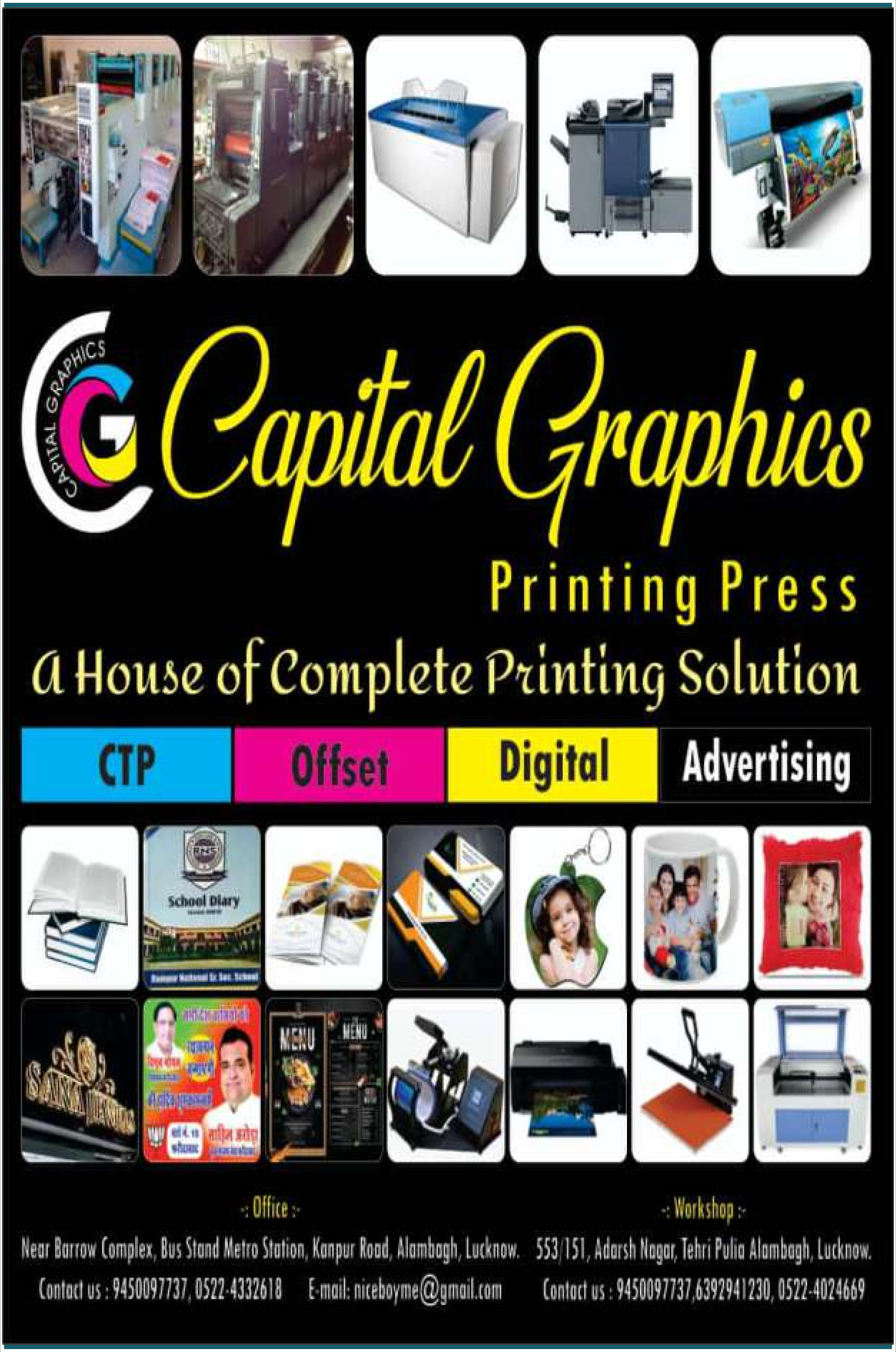
CAPITAL GRAPHICS
Capital Graphics
Printing Press
A House of Complete Printing Solution
CTP
Offset
Digital
Advertising
School Diary
MENU
MENU
-: Office :-
Near Barrow Complex, Bus Stand Metro Station, Kanpur Road, Alambagh, Lucknow.
Contact us : 9450097737, 0522-4332618
E-mail: niceboyme@gmail.com
-: Workshop :-
553/151, Adarsh Nagar, Tehri Pulia Alambagh, Lucknow.
Contact us : 9450097737,6392941230, 0522-4024669

लखनऊ जंक्शन

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

वर्ष–02 अंक–05 अप्रैल–2024

संपादक
अंजू सिंह
सहायक संपादक
मनोज गौतम
राजनीतिक संपादक
अनुराग पाण्डेय
सलाहकार संपादक
सुभाष चंद्र श्रीवास्तव
प्रवीण पाठक **दिल्ली ब्यूरो**
अनिल द्विवेदी **यूपी ब्यूरो**
मीनू कुमारी **उत्तराखण्ड ब्यूरो**
लखनऊ संवाददाता
राकेश कुमार मिश्र
अरविन्द कुमार
राजेश जोशी
विशेष संवाददाता (यूपी)
तारिक खान
विशेष संवाददाता (दिल्ली)
संदीप सिंह
विधि परामर्शदाता
महेन्द्र सिंह
मार्केटिंग मैनेजर
मोहन जोशी

एम.आई.जी. 47, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ (उ0प्र0)-226024
E-mail-lkojunction@gmail.com
दूरभाष- 7376547600, 0522-4232552

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक धर्मेन्द्र सिंह द्वारा नीलम प्रिंटिंग प्रेस 41 / 381, नरही, लखनऊ (उ0प्र0) से मुद्रित एवं एम.आई.जी. 47, सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ (उ0प्र0)-226024 से प्रकाशित

RNI No. UPHIN/2022/84386

इस अंक में प्रकाशित सामग्री के आंशिक या पूर्ण रूप से पुनर्प्रकाशन के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। लेखक के विचार व्यक्तिगत हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

इस अंक में

भारतीय जनता पार्टी माहौल पक्ष में, पर चुनौतियां भी कम नहीं

SACTEM का संकल्प अब हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक से नही होगी कोई मौत

कांग्रेस करेगी करिश्मा या चलेगा मोदी मैजिक

अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति–जीजाबाई

कांग्रेस की भगदड़ पार्टी के लिए चिंता की बात

वैसे देखा जाए तो कांग्रेस में भगदड़ मचने का सिलसिला 2014 के लोकसभा चुनावों के ऐलान के साथ ऐसा प्रारंभ हुआ कि यह सिलसिला आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक अनुमान के मुताबिक तब से लेकर अब तक कांग्रेस छोड़ने वालों में पार्टी के 15 पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित 1700 से अधिक छोटे-बड़े कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक-सांसद और राज्यसभा सदस्य शामिल हैं, जिनमें अधिकांश वे युवानेता हैं जो कभी राहुल की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। राहुल गांधी की दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा वास्तव में कांग्रेस छोड़ो यात्रा साबित हुई। क्योंकि इस दौरान ही सबसे अधिक नेताओं ने कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन थमा और हैरान कर देने वाली बात यह है कि कांग्रेस में मची भगदड़ को रोकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व खासतौर से गांधी परिवार व कांग्रेस के अभी भी अघोशित रूप सर्वेसर्वा कहे जाने वाले राहुल गांधी इसको रोकने के बजाए जाने वालों को ऐसे जाने दे रहे हैं, जैसे कि वे कभी कांग्रेस का हिस्सा रहे ही नहीं। सवाल यह है कि अगर यह कांग्रेस में मची भगदड़ नहीं थमी तो कांग्रेस में बचेगा ही कौन? वे नेता जो नेहरू-गांधी परिवार की परिक्रमा कर ऐसे दिल्ली जमे बैठे हैं, जिनके आगे प्रतिभाशाली और युवा नेता बेबस हैं। और अंतत में वे पार्टी ही छोड़ने पर विवश हो रहे हैं। जिसमें ताजा नाम शामिल है गौरव वल्लभ और बॉक्सर विजेंद्र सिंह का। वहीं संजय निरुमप को पार्टी ने ही निकाल दिया।

माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गौरव वल्लभ का भाजपा में जाना कांग्रेस के उसके चुनावी अभियान के लिए एक बड़ा झटका है। खासतौर से जब पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक सुप्रिया श्रीनेत भाजपा उम्मीदवार एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर निशाने पर हैं। एक अन्य वरिष्ठ प्रवक्ता पवन खेड़ा पर भी भाजपा ने प्रधानमंत्री का अपमान करने को लेकर आरोप लगाया था। इनके अलावा कांग्रेस के एक दूसरे वरिष्ठ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी पर अपनी टिप्पणी को लेकर आलोचना झेल रहे हैं।

गौरव वल्लभ से पहले जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला रीता बहुगुणा जोशी और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का साथ पकड़ा था। पार्टी छोड़ने वाले अधिकांश प्रवक्ताओं के अगर दर्द की बात करें तो कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादात्तर प्रवक्ताओं ने पार्टी नेतृत्व तक आसान पहुंच नहीं होने और वंशवाद का आरोप लगाकर पाला बदला है। शेरगिल ने कहा था कि उन्होंने एक साल तक गांधी परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन शीर्ष नेतृत्व के करीबी लोगों ने उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया। पूनावाला ने कहा था कि उन्हें वंशवाद के खिलाफ न बोलने के लिए मजबूर किया गया। इससे पहले, उन्होंने राहुल गांधी को कांग्रेस के लिए उनके विजन पर एक टीवी बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, हमारा मूल्यांकन योग्यता के आधार पर किया जा सकता है, सरनेम के आधार पर नहीं। रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि सोनिया गांधी वरिष्ठ नेताओं को सुनती थीं और उन्हें खुली छूट दे रखी थी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में ऐसा नहीं हुआ। प्रियंका चतुर्वेदी ने तब पद छोड़ दिया था, जब पार्टी ने उन कुछ नेताओं को बहाल कर दिया जिन पर उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौका देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस तरह वहीं इधर न्यूज चैनलों पर बहस के दौरान कभी कांग्रेस का पक्ष रखने वाले और सत्तारुढ़ भाजपा पर निशाना साधने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता अब भाजपाई बन कर अब केंद्र सरकार की बात रखते हैं और कांग्रेस और विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं।

अंजू सिंह

योगी सरकार के कार्यकाल के 7 साल पूरे, सीएम ने जनता का जताया आभार

'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश' के सृजन को समर्पित रहे 7 वर्ष : योगी आदित्यनाथ

प्रदेश वासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही सरकार

ब्यूरो कार्यालय

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 7 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को पूरा कर लिया है। इस अवसर पर सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि उनकी सरकार प्रदेशवासियों के हर सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प को 7 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 7 वर्षों में सबका साथ-सबका विकास के मंत्र के माध्यम से हर व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त हुई है। यह 7 वर्ष 'नए भारत के नए उत्तर प्रदेश' के सृजन को समर्पित रहे हैं। लोक-कल्याण के पथ पर चलते हुए डबल इंजन सरकार प्रदेश वासियों के हर सपने को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। प्रदेश की जनता-जनार्दन और सभी सहयोगियों का सहयोग-समर्थन के लिए आभार।"

भारतीय जनता पार्टी माहौल पक्ष में, पर चुनौतियां भी कम नहीं

फरीद वारसी

लोकसभा चुनाव से पहले हुए संसद के अंतिम बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शैली और अंदाज में विपक्ष खासतौर से कांग्रेस पर जो हमला बोला वहीं उससे इतर उन्होंने जिस जोश और खरोश से यह दावा किया कि "अबकी बार 400 के पार"। क्या यह नारा वास्तव में अपना व्यवहारिक रुप ले पाएगा, यह फिर यह एक चुनावी स्लोगन बन कर रह जाएगा। बहरहाल, यह तो लोकसभा चुनावों के परिणाम ही बताएंगें। लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि भाजपा की जो भी चुनावी तैयारियों हों, चाहे वह टिकट बांटना हो या फिर राजनीतिक रुप से खुद के सबसे अधिक मजबूत होने के बाद लगातार अपने नेतृत्व वाले राजग गठबंधन का आकार बढ़ाने के साथ विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोलने का काम हो, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि भाजपा की सारी चुनावी तैयारियां "अबकी बार 400 के पार" के प्रधानमंत्री के नारे को साकार करने की ही है। जैसा कि सर्वविदित है कि 18 वीं लोकसभा चुनावों को बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनावों का जिक्र होते ही लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चर्चा होना स्वभाविक है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का अपना राजनीतिक महत्व है। यही कारण है कि कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। और देखने वाली बात यह है कि मौजूदा समय में इस प्रदेश में अस्सी और नब्बे के दशक को बहुत पीछे छोड़ चुकी भाजपा की ही सरकार है और जिसके मुखिया है योगी आदित्यनाथ। जो अपनी विकासपरक, हिन्दुत्व वाली छवि से प्रदेश के पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्रियों कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और राम प्रकाश गुप्ता जैसों को कहीं बहुत पीछे छोड़ कर प्रदेश में भाजपा के लिए एक ऐसी लकीर खींच चुके हैं, जिसकी काट विपक्ष के पास नहीं है। जिसने बारे में यह चर्चा है कि योगी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ही केन्द्र में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनाने में अपना अहम योगदान अदा। यही कारण है कि इस बार भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य

निर्धारित कर चुनावी समर में अपनी ताल ठोंकी हैं।

सूबे में भाजपा द्वारा 80 में से 80 लोकसभा की सीटें जीतने के लक्ष्य पर राजनीति के जानकारों का कहना है कि भाजपा यह करिश्मा क्या कर पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। वैसे तो प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का कारनामा 1977 के लोकसभा चुनावों में जनता पार्टी द्वारा किया जा चुका है जब जनता पार्टी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश की सभी 85 सीटों पर जीत हासिल की थी। यह दौर कांग्रेस के जबरदस्त विरोध का था। बाद में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा चुनावों में सहानुभूति की लहर पर सवार कांग्रेस ने 85 में से 83 सीटें जीती थीं। जहां तक भाजपा का सवाल है तो मालूम हो कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 के लोकसभा चुनावों में किया था। जब उसने अपनी चुनावी रणनीति, चुनावी प्रबंधन और आक्रमक चुनाव प्रचार के सहारे 80 में से 73 सीटें जीत कर सबको आश्चर्य चकित कर दिया था। फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में 64 सीटें जीती थी। कांग्रेस के 1984 में पिछले 50 प्रतिशत वोट तो भाजपा ने 2019 के ही लोकसभा चुनावों में ही पार कर लिया था। और इस बार जैसा कि उल्लेखनीय है कि भाजपा ने सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। राजनीति के जानकार यह मानते हैं कि भाजपा अपने उपरोक्त लक्ष्य को हासिल कर सकती है। इसके पीछे वे अपने तर्कों को रेखांकित करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि सूबे में योगी आदित्य के नेतृत्व में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक विपक्ष के नाम पर जो शून्य उभरा है, वह भाजपा के पक्ष को मजबूत करता है। वहीं भाजपा ने बीते एक दशक से सामजिक और जातीय समीकरणों को साध कर रखा है। और दूसरी बड़ी बात यह कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद आम लोगों में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं का जो उभार पैदा हुआ है, वह कहीं न कहीं भाजपा को राजनीतिक रुप से चुनावी लाभ देगा। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या प्रेम से इतर सांकेतिक भाषा में ज्ञानवापी और मथुरा का प्रचार-प्रसार करना भाजपा को उसके निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकता है। तो दूसरी तरफ सीएए को लेकर ध्रुवीकरण की आशंका। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ लेता लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते भाजपा ने पिछड़ों पर जो दांव लगाया है। तो यही वजह है कि भाजपा के हक में प्रदेश में महौल बना जरूर है लेकिन यह भी सच है कि अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में भाजपा के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो यह कि भाजपा को अपने अति आत्मविश्वास के घोड़ों पर लगाम कसके रखनी होगी और दूसरे हारी हुई सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए कड़े प्रयास करने होंगे। मालूम हो कि भाजपा 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रदेश की कुल 16 सीटों पर चुनाव हारी थी। बाद में हुए उप चुनावों में भाजपा ने आजमगढ और रामपुर की सीट सपा छीन कर अपनी झोली में डाल ली थी। वहीं 10 से 12 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा की जीत का अंतर 15 हजार या उससे भी कम रहा था। इन उपरोक्त सीटों पर भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि चुनावी लड़ाई बहुत आसान नहीं है। फिर भी भाजपा को अगर इन सीटों पर जीत हासिल करनी है तो उसे इन सीटों पर अपने मत प्रतिशत को बढ़ाने की जरूरत रहेगी, जो एक तरह से भाजपा के लिए चुनौती ही होगी। यहां यह बताते चलें कि भाजपा प्रदेश की 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बची पांच सीटें उसने अपने सहयोगी दलों रालोद को दो, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, ओम प्रकाश राजभर व संजय निषाद की पार्टी को क्रमशः एक-एक सीट दी है। सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जीतने साथ सहयोगी दलों के वोटों का ट्रांसफर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में करने जैसी चुनौती भी भाजपा के ही हिस्से में हैं। वहीं भले ही यह कहा जा रहा हो कि भाजपा के सामने विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन जिसमें सपा और कांग्रेस शामिल हैं, उनकी संयुक्त ताकत भाजपा को चुनावी बांड, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर घेर सकती है। अगर भाजपा की यह रणनीति है कि मायावती की एकला चलो की राह इंडिया गठबंधन में सेंध लगा कर भाजपा का मार्ग आसान करेगी तो कहा यह भी जा रहा है कि मायावती की चुनावों में हथियार डाल देने वाली रणनीति से अब लोगबाग वाकिफ हो गए हैं। वहीं इन सबसे हट कर प्रदेश में सात चरणों में मतदान होंगे और यह समय सख्त गर्मी का होगा, ऐसे में भाजपा के सामने मतदाताओं को भी निकालने की चुनौती होगी। हां, भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों ने अगर यह सब चुनौतियों पार कर ली तो बेशक भाजपा प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहरा सकती है।

समाजवादी पार्टी

अखिलेश के नेतृत्व की होगी परीक्षा

अरविन्द यादव

राजनीति के मैदान के धुरंधर पहलवान रहे मुलायम सिंह के हाथों से निकल कर अखिलेश यादव के हाथों में आई समाजवादी पार्टी जो कि मौजूदा समय में प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं कि, अगर बात की जाए तो लगातार चार चुनाव 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव हार चुकी सपा और उसके मुखिया अखिलेश यादव के लिए इस बार के लोकसभा चुनाव काफी अहम हैं। और इसी के साथ यह कहा जा रहा है कि अगर सपा अखिलेश यादव के नेतृत्व में इन चुनावों में अपना मनमाफिक प्रदर्शन नहीं कर पाई तो सपा का हाल भी आने वालों दिनों में कांग्रेस और बसपा के जैसा ही हो सकता है। यानि कुल मिलाकर कहने का सार है कि अखिलेश यादव को इस बार इन लोकसभा चुनावों में अपने नेतृत्व को साबित ही करना होगा। हर चुनावों में अलग-अलग दलों से कभी कांग्रेस, कभी बसपा, कभी रालोद, कभी ओम प्रकाश राजभर तो कभी अपना दल कमेरावादी से गठबंधन का प्रयोग करने वाले अखिलेश यादव किसी भी चुनावों में गठबंधन और अपनी पार्टी की करारी हार को टाल नहीं सके, इसके बाद भी अखिलेश यादव इस बार इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी समर में कूदें हैं। गठबंधन के तहत सपा 63 और कांग्रेस मात्र 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और वहीं दूसरी ओर यह बात अलग है कि किन्हीं न किन्हीं कारणों के चलते अखिलेश यादव के पुराने सहयोगी मित्र जयंत चैधरी, ओमप्रकाश राजभर, अपना दल कमेरावादी और चंद्रशेखर आजाद अखिलेश से किनारा कर चुके हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अगर अखिलेश यादव चाहते तो वे ओमप्रकाश राजभर, अपना दल कमेरावादी

उदाहरण सामने है कि उसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश मे बल्कि समूचे देश में खुद के मजबूत होने के बाद भी अपने सहयोगी दलों को साथ जोड़ा और सीटों के बंटवारें के संबंध में उनकी भावनाओं को महत्व दिया। जबकि अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर पाए। इसी तरह सपा के वे नेता जो 2022 के विधानसभा चुनावों में सपा की सीटों को 111 तक ले जाने में अहम रहे वे भी एक-एक कर के सपा से किनारा कर उनसे दूर चले गए। संभवता अखिलेश में मुलायम सिंह यादव जैसे वे गुण तो नहीं हैं जिसके चलते मुलायम सिंह यादव न सिर्फ सहयोगी दलों को बल्कि अपने नाराज नेताओं को मनाने से लेकर उन्हें अपने साथ बांधे रखने में माहिर थे। वहीं इससे पूर्व सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने जिस माई वोट बैंक यानि मुस्लिम यादव के संयोजन से सपा को उत्तर प्रदेश की राजनीति में स्थापित कर स्वयं तीन बार और एक बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। अब उसी माई वोट बैंक को अखिलेश यादव ने कुछ दूसरे अंदाज में परिवर्तित कर पीडीए की रुप दिया। यानी पिछड़े, दलित और मुस्लिम। किन्तु राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए इसी पीडीए को कुछ इस तरह से नजरअंदाज किया गया कि सपा के संस्थापक सदस्य रहे सलीम शेरवानी जैसे दिग्गज नेता ने अखिलेश यादव की आलोचना करते हुए पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया। वहीं अखिलेश लाख दावा करें लेकिन दलित उनके पाले में आने से रहे, हां, बसपा से छिटक कर दलितों का एक बड़ा वर्ग भाजपा का हिस्सा बन गया है। पिछड़ो के नाम पर अखिलेश का सजातीय वोट बैक यादव तो 2014 के लोकसभा चुनावों से ही सपा से छिटक कर भाजपा की ओर चला गया। ऐसा क्यों हुआ अखिलेश ने यह कभी मंथन करने का प्रयास भी नहीं किया। रहा सवाल मुसल्मानों का तो ऐसा माना जा रहा है कि वह भी अब सपा का बंधुवा मजदूर बनने को तैयार नहीं हैं। यानी वोट बैंक के नाम पर सपा के हाथ बहुत हद तक खाली हैं। और उस पर सोने पर सुहागा यह कि मुकाबला भाजपा से। जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लोकसभा चुनावों के लिए सपा ने जब अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो सपा नेतृत्व द्वारा यादव परिवार को तरजीह दी गई। वह भी तब जब कि यह माना जा रहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर परिवारवादी पार्टियां ही खासतौर से रहेंगी। सपा का मुस्लिम चेहरा कहे जाने वाले आजम खां इनदिनों जेल में हैं और मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में आजम खां की नाराजगी और टिकट वितरण में उपजा विवाद सपा की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। वहीं यह कहा जा रहा कि भाजपा ने इस बार सपा के यादव बाहुल्य सीटों पर सेंध लगाने के लिए अपना अच्छा खासा होमवर्क किया है। वहीं देखने वाली बात यह है कि भाजपा की इसी रणनीति के चलते पिछले दो बार के लोकसभा चुनावों में सपा की सीटें घटने का क्रम शुरु हुआ था। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 9 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जो यादव बाहुल्य मानी जाती हैं। अखिलेश ने अपने गढ़ में भाजपा को रोकने के लिए क्या प्लान तैयार किया है, वह अभी स्पष्ट नहीं हैं। कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव के रणनीतिक कौशल की परीक्षा भी होगी। क्या अखिलेश इसमें स●●●

और चंद्रशेखर आजाद को अपने पाले से छिटकने न देते। भाजपा की ही

समाजवादी पार्टी

बहुजन समाज पार्टी
निरंतर हो रही हार के दंश से उभरना होगा

हरिओम मिश्रा

राजनीति के जानकार भले ही इस बात को स्वीकार करने में न हिचकते हों कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति की चतुर राजनेताओं में से एक हैं। वहीं इसके अतिरिक्त चार बार उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की मुख्यमंत्री बनी मायावती का सरकार चलाने का तरीका भी सबसे अलग रहा हो। लेकिन यह बात समझ से परे हैं कि बसपा संस्थापक कांशीराम से विरासत मे मिली पार्टी बसपा को सूबे की राजनीति में एक मजबूत विकल्प बनाने के बाद उसे उसी स्वरुप में बरकरार नहीं रख सकी। हालांकि एक वक्त में ब्राहम्ण-दलित और दलित-मुस्लिम जैसे उनके समीकरण काफी सफल रहे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ब्राहम्ण और मुसलमान क्या अब तो दलित भी बसपा के खेमें में उतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं, जितना की कभी हुआ करते थे। सच तो यही है कि दलित वर्ग ही बसपा की सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था। जिसको कांशीराम ने बहुत ही जतन से कांग्रेस से खींच कर बसपा से जोड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक हैं। जिसमें जाटव, दुसाध और धूसिया आदि भी शामिल हैं। और इसमें मायावती का जाटव वोट बैंक करीब 29.4 प्रतिशत हैं। कहा जाता है कि 2014 के लोकसभा के चुनावी समर में उतरने से पहले भाजपा के चुनावी रणनीतिकारों खासतौर से उस समय के उत्तर प्रदेश के भाजपा प्रभारी रहे अमितशाह ने प्रदेश में भाजपा के अकल्पनीय जीत दिलाने के लिए सपा के यादवों और बसपा के दलित वोट बैंक मे सेंध मारी करने की जो नीति बनाई थी, वह इस हद तक सफल रही कि वोट बैंक नाम पर सपा और बसपा एक हद तक हाथ रिक्त हो गए। फिर केन्द्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यादवों से लेकर दलितों को जब अपनी योजनओं में तरजीह दी तो यह वर्ग पूरी तरह से भाजपा

के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अतीत के पन्ने पलट कर देखे तो बसपा की दुर्गति की शुरुआत उस वक्त हुई जब पांच साल की बहुमत वाली सत्ता चलाने के बाद बसपा की 2012 के विधानसभा चुनावों में बहुत ही शर्मनाक हार हुई। 2014 के लोकसभा चुनावों में बसपा का खाता तक नहीं खुला। 2017 व 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के साथ ही बसपा की सीटों कम होने का सिलसिला जारी रहा। शायद इससे सबक सीखते हुए बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनावों में अपनी पुरानी रंजिश भुलाते हुए सपा के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन में रालोद भी शामिल थी। इस गठबंधन का बसपा को फायदा मिला और उसने दस लोकसभा सीटें जीती, वहीं सपा ने पांच वह भी पांचों यादव परिवार के लोग ही जीते। जबकि रालोद का खाता तक नहीं खुला था। इसके बाद भी न जाने क्यों लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही मायावती ने सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर सबको चैका दिया। कहा जाता है कि अगर यह गठबंधन कायम रहता तो 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम कुछ और ही होते, जहां बसपा को सिर्फ एक सीट ही मिली थी।

बहरहाल, इस बार के लोकसभा चुनावों में मायावती ने गठबंधन से परहेज करते हुए एकला चलो की रणनीति पर चलते हुए अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। किन्तु उन पर आरोप यह भी लग रहे हैं कि उन्होंने भाजपा के दबाव में इंडिया गठबंधन से अपनी दूरी बनाए रखी है। जबकि कांग्रेस के प्रयास तो यही थे कि बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। इसके लिए कांग्रेस तो अखिलेश की नाराजगी तक को नजरअंदाज कर रही थी। भाजपा से सांठ-गांठ होने के आरोप बसपा पर सिर्फ चुनावों के मौके पर ही नहीं लगते, बल्कि चुनाव न होने पर बसपा का पूरी तरह से खामोश बने रहना, चुनावों में अपनी आक्रमकता न दिखाना या बहुत अधिक मुखर न होना जैसे कारक संदेह तो पैदा करते है ही। सबसे बड़ी बात यह कि बसपा की इन्हीं बातों के कारण आज बसपा के दिग्गज नेता बसपा का साथ छोड़कर दूसरे और दलों खासतौर से भाजपा की ओर पलायन कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं में भी निराशा है। जिसने बसपा को और भी कमजोर करने का काम किया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर माना जा रहा है कि मायावती की अकेले चुनाव लड़ने के पीछे की रणनीति सूबे में चुनावी मुकाबले का त्रिकोणीय बनाते हुए बसपा को वापस उस मुकाम पर लाने की है, जो कभी बसपा की पहचान हुआ करती थी। इसके लिए मायावती ने एक बार फिर से दलित-मुस्लिम कार्ड खेला है। लेकिन लगातार गिरते वोट शेयर के बीच क्या मायावती इस बार बसपा की हार की नियति तोड़ पाएंगी। फिर अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने एक तरह से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया है, क्या वे लोकसभा चुनावों में बसपा के लिए करिश्माई साबित होंगे। यह देखने की बात होगी। ●●●

कांग्रेस
अस्तित्व बचाने का संकट

उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद कांग्रेस का कभी गढ़ हुआ करता था। विड़बना यह है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में आजादी के बाद यह पहला ऐसा मौका है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस सबसे कम मात्र 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जो कि उसे इंडिया गठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टी सपा से बहुत कहने सुनने के बाद मिली। वरना सपा ने पहले कांग्रेस को 12 सीटें देकर उसे टरकाने का काम किया था। बहरहाल, जिन 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव के मैदान में हैं, उनमें से अधिकांश सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पूर्व के चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशियों की जमानतें तक जब्त हो चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में सिर्फ सोनिया ही उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत सकीं थीं, जबकि पार्टी अध्यक्ष होते हुए राहुल गांधी तक चुनाव हार कर इंदिरा गांधी की बराबरी कर चुके हैं। अब तो सोनिया गांधी भी रायबरेली से पलायन कर राजस्थान से होते हुए राज्यसभा जा पहुंची हैं। वहीं इससे नए प्रयोग के तहत राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन वे भी नाकाम साबित हुई इन चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत गिर कर 6.36 तक आ गया और 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट प्रतिशत 2.33 तक जा गिरा और कांग्रेस की सीटें सात से घट कर दो ही रह गई। यानि इन चुनावों में प्रियंका का करिश्मा भी धाराशाही हो गया। यही कारण रहे कि बीते दिनों उन्हें भी उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी से मुक्त कर अविनाश पांडे को जिम्मेदारी दी गई। पहले सोनिया फिर प्रियंका और अब राहुल का अमेठी से लेकर सस्पेंस यानी सूबे से नेहरु-गांधी परिवार का भंग होता मोह, इस ओर इशारा करता है कि कांग्रेस ने प्रदेश में अंपने हथियार ही डाल दिए हैं। वहीं इस बार के लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भाजपा को हराने

विकास शुक्ला

का दावा करने वाले राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने के नाम पर अपने वजूद को बचाने का प्रयास कर रही है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगी। यह बड़ा सवाल कांग्रेस और उसके नेतृत्व के सामने हैं।

देश के सबसे बड़े सूबे और राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की दुगर्ति और लगातार उसके सिमटने का दौर उस वक्त प्रारंभ हुआ जब 1989 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी की सरकार की हार हुई। कांग्रेस ने वहां से जो गिरना शुरु किया वह सिलसिला आज तक जारी है। एक समय कांग्रेस के पास ब्राहम्ण, मुसलमान और दलित एक साथ हुआ करते थे। लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेतृत्व की कुछ ऐसी नीतियां रहीं कि कांग्रेस का यह सारा वोटबैंक कांग्रेस से छिटक कर भाजपा, सपा और बसपा की ओर चला गया। देखने वाली बात यह है कि अपने इस वोट बैंक को कभी वापस लाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। यहां तक कि सोनिया और राहुल गांधी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, कि जिससे प्रदेश में कांग्रेस के बुरे दिन खत्म होते दिखते। सिवाए बड़ी-बड़ी बातों के खासतौर से वह भी राहुल गांधी की ओर से जो कुछ पिछले

दो दशकों मे की गई। अगर बयानबाजी कम और जमीनी प्रयास अधिक होते तो शायद कांग्रेस के पैर इस हद तक सूबे से और न उखडे होते जो स्थिति मौजूदा समय में हैं।

वर्तमान समय मे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो निर्मम सत्य यह है कि कांग्रेस के पास न नेता है और और ना ही कोई ऐसी नीति जो प्रदेश में कांग्रेस के हालात बदल सके। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें ही बनाया जाता है जो नेतृत्व की जी हुजुरी कर सके और बाद में चुनाव मे मिली हार के बाद उन पर आसानी से हार का ठीकरा फोड़ कर अपनी जवाबदेही से बचा जा सके। यह सिलसिला पिछले तीन दषकों से भी अधिक समय से हो रहा है। कार्यकर्ताओं से लेकर मतदाताओं का भरोसा जीतने का कांग्रेस के पास प्रदेश मे कोई मजबूत त्रंत नहीं है। सांगठनिक ढांचा कमजोर और प्रत्याशियों के व्यक्तिगत प्रबंधन पर निर्भरता के कारण ही कांग्रेस का लगातार जनाधार घटा और हर प्रयोग स्वाहा हुए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में सपा और कांग्रेस एक साथ थे। उसके बाद के परिणाम किसी से छिपे नहीं हैं। और यही दोनों एक बार फिर से इस बार के लोकसभा चुनावों में एक साथ हैं, कांग्रेस की कमजोर और दयनीय स्थिति को देखते हुए चुनाव नतीजे क्या होंगे, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरुरत नहीं।

●●●

राष्ट्रीय लोक दल
...और बड़े राजनीतिक फायदे के लिए पलट गई चवन्नी

आर0 के0 मिश्रा

लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान जब जीवित थे, तो उनके बारे में लालू प्रसाद यादव का कहना था कि वे ही असली मौसम वैज्ञानिक हैं, जो हवा का रुख भांप कर सत्ता के लिए गठबंधन बदलने में माहिर हैं। लेकिन यह कहावत पूरी तरह से रालोद के संस्थापक रहे छोटे चैधरी के नाम से मशहूर चैधरी अजित सिंह पर भी पूरी तरह से लागू होती है। जो सत्ता की खातिर गठबंधन बदलने में राम विलास पासवान से कहीं अधिक माहिर थे। और यही कारण रहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह से विरासत मे मिली राजनीतिक पूंजी को अजित सिंह संजो कर नहीं रख सके। यह किसी से छिपा नहीं हैं कि जाट बाहुल्य क्षेत्र कहे जाने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में चैधरी चरण सिंह के परिवार का अपना एक अलग वर्चस्व रहा है। पर, जाट और मुस्लिम समीकरण की राजनीति को अजित सिंह के बार-बार पाला बदलने की राजनीति से इतना अधिक अप्रासंगिक कर दिया कि रालोद की क्षेत्रीय स्तर की मान्यता भी चली गई। बाद में अजित सिंह के निधन के बाद चैधरी घराने के वारिस जयंत चैधरी के हाथों पार्टी की बागडोर आई, यह वक्त पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भरा था। जयंत ने पार्टी को दुबारा खड़ा करने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की और सपा के साथ मिल कर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। लेकिन रालोद का खाता नहीं खुला। सपा के साथ उनका गठबंधन विधानसभा चुनाव में बना रहा जहां उन्हें छह सीटें मिली। और बाद में जयंत चैधरी सपा के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। यहां यह बताते चलें कि 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जयंत चैधरी को अपने साथ लाने के प्रयास किए लेकिन जयंत चैधरी ने यह कह कर इंकार कर दिया कि वह कोई चवन्नी छाप नेता नहीं हैं, जो पलट जाएं। तब यह लगा कि जयंत चैधरी अपने पिता दिवंगत चैधरी अजित सिंह की तरह गठबंधन बदलने की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हैं। वहीं 2022 के विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद जयंत को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिलने लगा इंडिया गठबंधन ने उन्हें तरजीह दी। तो वहीं अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत लोकसभा चुनावों के लिए उन्हें सात सीटें देने के संकेत दिए। जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने समीकरणों को साधने के लिए भाजपा ने एक बार फिर जयंत चैधरी को साधने के लिए दूर का दांव चलते हुए केंन्द्र की मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, बस फिर क्या था, जिसके बाद जयंत चैधरी ने मोदी सरकार के इस फैसले से प्रभावित होकर इंडिया गठबंधन छोड़ भाजपानीत राजग गठबंधन में जाने का निर्णय लेकर अपने पिता चैधरी अजित सिंह की यादें ताजा कर दी। और इस तरह से चवन्नी पलट गई। जानकारों की माने तो जयंत चैधरी को इंडिया गठबंधन की तुलना में भाजपा नीत राजग में अपने लिए राजनीतिक फायदा अधिक नजर आया। भले ही भाजपा ने गठबंधन के तहत रालोद को दो सीटें दी हों, योगी सरकार में रालोद को भागेदारी देने के साथ ही जयंत को यह भरोसा दिया हो कि लोकसभा चुनावों के बाद उन्हें केन्द्र में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि दरअसल जयंत भी नीतीश कुमार की तरह यह बात भांप गए कि इंडिया गठबंधन की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की जीत की संभावनाएं कहीं बेहतर हैं। इसलिए उन्हें गठबंधन बदलने का निर्णय लेने के लिए ज्यादा सोच विचार नहीं किया और प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए राजग की राह पकड़ी। अब देखना यह होगा कि लोकसभा चुनावों में पश्चिम उत्तर प्रदेश में गठबंधन बदलने का फायदा जयंत को मिलता है या नहीं, वह भी तब जबकि मोदी सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी एक बार फिर से सतह पर प्रकट हुई हैं।●●●

पहले सोरेन और अब केजरीवाल

संदीप सिंह

जैसा कि सर्वविदित है कि देश अपनी आजादी के 77 साल में प्रवेश कर गया है और इसी साल देश के 18 वें लोकसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले दो राज्यों के मुख्यमंत्री पहले आदिवासी बाहुल्य राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बाद में देश की राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरंविद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार हुए। वहीं इससे पहले दिल्ली के ही उपमुख्यमंत्री मनीश सिसौदिया को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। खैर, उन्हें गिरफ्तार हुए तो एक साल से भी अधिक समय हो चुका है। यहां यह कहा जा सकता है कि उपरोक्त नेताओं की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुचर्चित नीति का प्रकटीकरण हैं। यही कारण है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वाजनिक रुप से यह कहते हैं कि भ्रष्ट नेताओं को देश और आम जनता से लूटा हुआ पैसा उन्हें वापस ही करना पड़ेगा, और ऐसा ही होकर रहेगा, यह मोदी की गारंटी है तो यहां पर भ्रष्टाचार के मोदी सरकार की नीति पर संदेह भले ही न किया जाता हो लेकिन कुछ ऐसे सवाल जरूर हैं जो विचलित करते हैं। जिसकी चर्चा फिलहाल आगे की जाएगी। बाद पहले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी की तो, यह पहला मौका है जब देश के किसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यूं गिरफ्तार किया गया हो। निसंदेह यह हर कोई चाहता है कि देश को दीमक की तरह चाट रहे भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा हो। और राजनीति का क्षेत्र पूरी तरह से ईमानदारी का प्रतीक बना रहे। लेकिन क्या यह उचित है कि यूं इस तरह से संवैधानिक पदों बैठे यानी मुख्यमंत्रियों को इस तरह से गिरफ्तार किया जाए। यहां पर यह बात साफ कर देना जरूरी है कि यहां पर किसी भी सूरत में सोरने या केजरीवाल का समर्थन नहीं किया जा रहा है। लेकिन यूं एक नहीं, बल्कि दो-दो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी से जो सवाल पैदा हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। वह इसलिए क्योंकि डर तो इस बात का है कि यह चलन कहीं आगे चलकर सत्ता की राजनीति में बदले की कार्रवाही का पलटवार न बन जाए। यह संदेह अकारण ही नहीं व्यक्त किया जा रहा है। यह ठीक है कि किसी भी दल या गठबंधन के लिए सत्ता भले ही लंबे समय के लिए हो सकती है, लेकिन किसी के लिए स्थाई जागीर जैसी नहीं होती है। यह लोकतंत्र का ताकाजा है कि आज नहीं तो कल सत्ता बदलती है। और जब सत्ता बदलती है तो विपक्ष के सत्ता में आने के बाद उसे पूर्व

की सत्ता से मिले अपने अपने घाव याद आते हैं और ऐसे में जख्म ताजा होना स्वाभाविक है। अभी ज्यादा दूर जाने की जरुरत नहीं हैं। बात बीते दिनों की है जब इंकमटैक्स द्वारा कांग्रेस को टैक्स जमा करने की नोटिस थमाई गई तो राहुल गांधी ने एक संवाददाता सम्मेलन में लगभग बिफरते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद यही सबकुछ भाजपा के साथ किया जाएगा। लोगों का शायद यह याद हो कि तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता और एम करुणानिधि का राजनीतिक बैर कभी किसी से छिपा नहीं रहा। जब एक बार जयललिता सत्ता में वापस आईं तो उन्होंने बदले की कार्रवाही करते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे एम. करुणानिधि को रात में सोते हुए पुलिस से उठवा लिया था। जिसकी सारे देश मे आलोचना हुई थी। सवाल यह है कि ऐसा कुछ बोया ही क्यों जाए तो सत्ता न रहने पर काटने की नौबत आए। कम से कम सत्ता पक्ष को इस ओर सोचने की जरुरत है। नहीं तो विपक्ष द्वारा उस पर केन्द्रीय एजेंसियों के गलत इस्तेमाल कर तानाशाही के जो आरोप लग रहे हैं, वे आगे चल कर राजनीति से प्रेरित न होकर कहीं सत्य न प्रतीत होने लगें। फिर केजरीवाल के उन दावों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि जिसके तहत वे भाजपा पर आरोप लगाते हुए यह कहने से संकोच नहीं करते हैं कि उनकी पार्टी को तोड़ने और आप की सरकार को गिराने के लिए भाजपा हर हथकंडे अपना रही है।

वहीं इधर, यह कम चिंता की बात नहीं है कि सोरेन की गिरफ्तारी पर न सही, लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी होने के बाद जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने जैसा काम किया। यह बात अलग है कि उपरोक्त देशों की प्रतिक्रियाओं का भारत की सरकार ने उन्हें भारत में उनकी दखल अंदांजी बात कर अपना सख्त ऐतराज जताया। लेकिन इसके बाद भी यूएनओ ने अपनी प्रतिक्रिया का इजहार कर यहां तक कह दिया कि हमें "उम्मीद है कि भारत तथा किसी भी अन्य देश में, जहां चुनाव हो रहे हैं, लोगों के "राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी और हर कोई एक "स्वतंत्र व निष्पक्ष माहौल में मतदान कर पाएगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सारी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। ऐसी बातों पर ताली बजाने वालों को इस ओर भी गौर करने की जरूरत है कि चुनाव के मौके पर भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पर जो अंदाज अपनाया जा रहा है, वह दुनिया के कुछ देश द्वारा संदेह की नजरों से भी देखा जा रहा है।

वहीं बात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से पैदा हुए सवालों की तो विपक्ष के साथ-साथ नागरिक समाज का एक बड़ा वर्ग इस बात को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है कि उपरोक्त मुहिम के निशाने पर सिर्फ विपक्ष के नेता ही क्यों? सत्ता पक्ष या उसके सहयोगी दलों के नेताओं को इस मामले में आखिर क्यों नजरअंदाज किया जाता है। फिर भ्रष्टाचार तो आखिर भ्रष्टाचार ही है। इस पर दोहरे मापदंड क्यों? वहीं विपक्ष का वह कोई नेता जिस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं तो उसे भाजपा क्यों और किस आधार पर पवित्र मान कर अपने दल मे शामिल करने के लिए लाल कालीन बिछा देती है। जो कि पिछले एक दशक से देखने को मिल रहा है। यहां तक कि टिकट देने और राज्यसभा तक भेजने में ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है।

रहा सवाल शराब घोटले मे केजरीवाल की गिरफ्तारी का तो यह सर्वविदित है कि सरकारों के लिए शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व उसकी आय का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। वहीं देखने वाली बात यह है कि शराब पर टैक्स बढ़े या फिर घटे, इससे शराब पीने वालों पर कोई असर नहीं होता है। और यही कारण है कि विभिन्न राज्य सरकारें अपने हिसाब से शराब पर टैक्स लगा कर उसे वसूलने का काम करती हैं। तभी तो दिल्ली की केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार अपने राज्य में नई शराब नीति लेकर आई। पर, उसकी यह शराब नीति 'आप' के लिए गले की फांस बन गई। अब तक उसके तीन बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। यह ठीक है कि ईडी के तौर-तरीकों पर सवाल पैदा हो रहे हैं लेकिन इससे किसी की बेगुनाही साबित नहीं होती है। फिर केजरीवाल के लिए तो यह खासतौर से अहम है क्योंकि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चले आंदोलन से निकले लोग अगर राजनीति में आते हैं तो और उसके बाद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते हैं तो यह उनके साथ-साथ देश की राजनीति के लिए भी चिंता की बात होती है। फिर देखने वाली बात यह है कि राजनीति में आने के बाद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत पहले से ही स्थापित राजनीति से इतर गैर-पारंपरिक तौर तरीके अपना कर की। गरीब और आम आदमी के हितों की बात की। यही कारण रहा कि प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता लगातार उन्हें दोबार मिली। पंजाब में भी कांग्रेस को बेदखल कर सत्ता में आए। कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता का सुख रोग और खासतौर से महंगी चुनावी व्यवस्था ने तो केजरीवाल को सत्ता से जेल तक तो नहीं पहुंचा दिया। वहीं दूसरी ओर शराब घोटले का असली सच क्या है, उसके सामने आने के बाद ही पता चलेगा लेकिन वहीं दूसरी ओर इस लेख के लिखे जाने तक अब जबकि केजरीवाल गिरफ्तार ही हो चुके हैं तो उन्हें जरुरी कानूनी प्रक्रियाओं से रुबरु होना ही पड़ेगा। ●●●

राजनीतिक अपराधीकरण की एक कहानी का अंत

उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन ऐसी उर्वरक है कि जहां इस प्रदेश ने देश को नौ प्रधानमंत्री दिए और इसके अलावा एक से बढ़कर एक ऐसे नेता दिए जिन्होंने प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। पर वहीं दूसरी ओर एक कड़वा सच यह भी है कि इसी प्रदेश की राजनीतिक जमीन बाहुबलियों के लिए भी काफी मुफीद रही। उनका अपना खौफ, प्रभाव, धाक और हनक ने प्रदेश के कुछ राजनीतिक दलों के लिए संजीवनी बनने का काम किया। तमाम ऐसे बाहुबलि खुद तो अपने अपराध को संरक्षण देने के लिए सफेदपोश नेता तो बने ही संबंधित राजनीतिक दलों के लिए भी उपयोगी साधन बन गए। और यहीं से राजनीतिक अपराधी करण की एक नई कहानी शुरु हुई। जो खूब फली-फूली। और इसी कहानी का एक बड़ा नाम और चेहरा हुआ करता था मुख्तार अंसारी। कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति खास तौर से गाजीपुर और मऊ में राजनीतिक समीकरण अपने हक में साधने के लिए मुख्तार अंसारी का बस नाम ही काफी था। और समय के साथ इस क्षेत्र में अंसारी परिवार की ऐसी तूती बोलती थी कि जिनका निर्णय पत्थर की लकीर हुआ करता था। लेकिन कहते हैं कि सब दिन एक समान नहीं होते हैं। वक्त का पहिया घूमता जरूर है। और वह अपने नियमों के अनुसार जब घूमा तो वह राजीतिक अपराधी करण से युक्त खौफ का साम्राज्य अब बिखरने के कगार पर पहुंचता दिख रहा है जिसकी एक गूंज ही बस काफी हुआ करती थी।

गौरतलब है कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना और बाहुबलि नेता मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार अंसारी लंबे समय से जेल में बंद थे। उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। जहां तक मुख्तार अंसारी का सवाल है तो मुख्तार अंसारी अंसारी गाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद युसूफपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में 3 जून 1963 को हुआ था। उसके पिता का नाम सुबाहउल्लाह अंसारी और मां का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र दिया गया था। जबकि मुख्तार अंसारी के पिता सुबहानउल्लाह अंसारी गाजीपुर की राजनीति में सक्रिय रहे थे। उनकी बेहद साफ-सुथरी छवि रही है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में तो मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। रहा सवाल मुख्तार अंसारी का तो उसने अपराध की

फरीद वारसी

दुनिया में अपना वर्चस्व बनाया और इसी को जरिया बनाकर राजनीति की सीढ़ियां चढ़ता गया। आखिरकार वह कानून से और अधिक समय तक नहीं बच सका और 2005 से जेल में सजा काट रहा था।

राजनीति की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने अपना दबदबा बनाकर रखा था। उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इसके बावजूद वह चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक रहा। उसने 15 साल से ज्यादा वक्त जेल में काटा। सन 1996, 2002, 2007, 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनावों में मुख्तार अंसारी को जीत मिली। तीन विधानसभा चुनावों में मुख्तार अंसारी ने जेल में रहकर ही जीत हासिल की थी। पिछले ही विधानसभा चुनावों 2022 की अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी ने जेल में बंद रहने के बाद भी अपने बेटे और भतीजे को चुनाव जीतवा दिया।

मुख्तार अंसारी के अपराधिक जीवन की अगर बात करें तो सन 1988 में एक ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी का नाम पहली बार सामने आया था। इसी दौरान बनारस में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। इसमें भी मुख्तार का ही नाम सामने आया। साल 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर ब्रजेश सिंह गैंग ने कब्जा शुरु कर दिया था। अपना वर्चस्व को बनाए रखने के लिए मुख्तार अंसारी के गिरोह से उसका सामना हुआ। साल 1991 में चंदौली में मुख्तार को पुलिस ने पकड़ लिया। उस पर रास्ते में दो पुलिस कर्मियों को गोली मारकर फरार होने का आरोप है। उस पर 1991 में कांग्रेस नेता अजय राय की हत्या का भी आरोप लगा। इसमें अंसारी समेत पांच लोगों पर मुकद्दमा दर्ज किया गया। इसके बाद उसने सरकारी ठेके, शराब के ठेके, कोयला के काले कारोबार को बाहर रहकर संभालना शुरु किया। सन 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले के मामले में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया।

इसी दौरान 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार एमएलए बना। जैसा कि उल्लेखनीय है कि वह कुल पांच बार विधायक रहा। सन 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार का नाम अपराध की दुनिया में छा गया। कहा जाता है कि 2002 में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। इसमें मुख्तार अंसारी के तीन लोग मारे गए। अक्टूबर 2005 में मऊ में हिंसा भड़की। इसके बाद उस पर कई आरोप लगे, जिन्हें खारिज कर दिया गया।

इसी दौरान मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है राजनीतिक रसूख की लड़ाई में मुख्तार ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की एके 47 से हत्या करा दी। उस पर 2010 में राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर-मऊ क्षेत्र से भाग निकला था। जिसे साल 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगा दिया था। मुख्तार के खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे

कई आपराधिक मामले दर्ज थे। मुख्तार अंसारी पर कुल 60 से ज्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें अधिकतर मामले गाजीपुर के थे।

एक समय अपनी बाहुबलि राजनीति के कारण सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दलों के दुलारे रहे मुख्तार अंसारी के बारे में अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि साल 2017 में उप्र में भाजपा की सरकार के सत्ता में आने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के एक साल बाद मऊ से पांच बार विधायक रहे अंसारी को सबसे बड़ा झटका तब लगा, जब विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या कर दी गई। वहीं झांसी जेल से बागपत जेल लाए जाने के एक दिन बाद बजरंगी की नौ जुलाई, 2018 को एक अन्य गैंगस्टर सुनील राठी ने जेल में ही हत्या कर दी थी। जब उसके सहयोगी मारे जा रहे थे, तो राज्य सरकार ने मुख्तार पर दबाव बनाए रखा। पुलिस मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पुलिस ने अंसारी से जुड़े 292 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। दिसंबर 2023 तक इनमें से कई सहयोगियों पर गिरोहबंद अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि 186 को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों के अनुसार, सरकार ने राज्य भर में मुख्तार अंसारी या उसके सहयोगियों से जुड़ी करोड़ों की संपत्तियों को भी जब्त कर लिया और उसके आपराधिक साम्राज्य का समर्थन करने वालों की अवैध कमाई को भी जब्त कर उसके आर्थिक नेटवर्क को भी ध्वस्त कर दिया।

यह सर्वविदित है कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में आए और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने सदन से लेकर सर्वाजनिक रुप से इस बात का ऐलान किया था कि प्रदेश में कानून का राज कायम होगा और अब सूबे के माफियाओं, दंबगों और अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। या तो वे सुधर जाए या फिर उन्हें सुधार दिया जाएगा। हालांकि कि अपराधियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस सख्त रवैया के आलोचाना भी हुई थी लेकिन यह बात अलग है कि किसी भी आलोचनाओं की चिंता किए बिना मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया था, उस पर वे अमल करते हुए दिख रहे हैं। और यही कारण है कि कानून व्यवस्था में सुधार के बाद प्रदेश की जो तस्वीर हर क्षेत्र में बदली है, वह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की है। और यही कारण है कि न सिर्फ इस लोकसभा चुनावों में बल्कि पिछले विधानसभा चुनावों से ही चुनावी राजनीति में बाहुबलियों का जोर कहीं नहीं दिख रहा है। प्रदेश सरकार, पुलिस और अदालतों की सक्रियता के कारण राजनीति मे बाहुबलियों का दखल अब करीब-करीब खत्म होता दिख रहा है। और इसका श्रेय निसंदेह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। वहीं इधर, राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि अब जबकि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो उसके गढ़ कहे जाने वाले गाजीपुर, मऊ की घोसी विधानसभा सीट और बलिया संसदीय सीट तक त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना लगभग समाप्त हो गई है। वहीं यह माना जा रहा है कि भाजपा राजनीति में अपराधी करण को खत्म करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडे को लेकर जब मतदाताओं के बीच जाएगी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष खासतौर से सपा और बसपा द्वारा अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत को मुसलमानों में डर पैदा करने की राजनीति को रुपांतरित कर भाजपा विरोधी वोटों का धुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनावों के चलते ही सपा-बसपा जैसे राजनीतिक अपराधीकरण के हितैशी दलों ने मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच की मांग कर अपनी तुष्टिकरण की राजनीतिक की शुरुआत भी कर दी है। वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ की माफियाओं के खिलाफ मुहिम पहले से ही जारी है तो कहा यह जा रहा है कि इसका प्रभाव काफी हक तक लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों खासतौर से बलिया और मऊ तक भाजपा के हक में दिख सकता है। ●●●

उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत करने के पाँच बुनियादी कदम

बिभू प्रसाद महापात्रा
कार्यकारी निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

मिलेनियल्स (80 और 90 के दशक में पैदा होने वाली पीढ़ी), प्रोफ़ेशनल्स और सेवानिवृत्त लोग उज्ज्वल भविष्य के लिए बचत करने के तरीकों और माध्यमों की तलाश कर रहे हैं। अनगिनत पुस्तकों ने पैसे बचाने के माध्यमों और तरीकों के बारे में बताने के लिए दर्शन, आर्थिक सिद्धांतों और गुलाबी आंकड़ों (संभावनाओं से भरपूर आंकड़े) की तारीफ़ें की हैं। लेकिन ज्ञान की मौजूदगी के बावजूद वित्तीय स्थिरता का मार्ग धुंधला और उलझन से भरा हुआ है।

हाल के डेटा संकेत देते हैं कि पैसे बचाने के रुझान में गिरावट आई है। 2021-23 के बीच वित्तीय बचत (GDP) पर RBI के आंकड़ों ने 7.2% से 5.1% तक गिरावट का संकेत दिया है। 2022 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पिछले वर्ष में घरेलू बचत की तुलना में 1.60 लाख करोड़ रुपएकी बचत में गिरावट देखी है। NSO के आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पर्सनल लोन में तेज़ी आई है।

आदर्श रूप से, वित्तीय समृद्धि को पीढ़ीगत श्रेणियों में विभाजित करने के बजाय पाँच समाधानों के रूप में देखना बेहतर है। इन बुनियादी चरणों में शामिल हैं–बजट बनाना, कर्ज़ चुकाने को प्राथमिकता देना, बचत करना, विविधता लाना और बीमा लेना। इन आदतों का पालन करने लोगों को सुरक्षित भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलनी चाहिए।

अच्छी वित्तीय समृद्धि योजना के लिए अच्छी तरह से बजट बनाना काफ़ी अहम होता है। उदाहरण के लिए, कोई मिलेनियल, बचत की कमी की वजह से परेशान हो सकता क्योंकि उसने अपने स्टूडेंट लोन के बारे में ध्यान से योजना नहीं बनाई थी। इसी तरह, कोई पेशेवर अपने होम लोन को लेकर EMI की गलत गणना कर सकता है। गलतियों और कमियों से भरा बजट न सिर्फ़ बचत करने की क्षमता पर असर डालता है, बल्कि किसी व्यक्ति को अपने प्रियजनों से उलझने के लिए भी मजबूर कर सकता है।

एक बार जब व्यक्ति अपनी मासिक कमाई और खर्चों का बजट बना लेता है, तो ज़रुरतों, इच्छाओं और बचत को पूरा करने के लिए उसे 50, 30 और 20 प्रतिशत अनुपात में विभाजित करना एक अच्छा विचार होगा। 50/30/20 नियम टैक्स के बाद के पैसे बचाने पर एलिज़ाबेथ वॉरेन के दर्शन पर आधारित है। उदाहरण के लिए, 100,000 रुपए की टैक्स के बाद इनकम के परिणामस्वरुप प्रतिमाह 20,000 रुपए की बचत हो सकती है। एक अनुशासित तरीके के परिणाम स्वरुप वर्ष के आखिर में 2,40,000 रुपए की सावधि जमा होने की संभावना है। डिजिटल के इस दौर में,

पर्सनल लोन, क्रेडिट-कार्ड या "बाद में भुगतान करें" जैसी स्कीम की मौजूदगी के साथ अनुशासन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऐसे मामलों में, किसी को कर्ज़ देने की योजना की रणनीति बनाने की ज़रुरत हो सकती है। इसमें साधारण चीज़ें शामिल हो सकती हैं जैसे ब्याज दरों की तुलना करना, बातचीत करना और यहाँ तक कि स्थायी रीपेमेंट सुनिश्चित करने के लिए एक शेड्यूल को अंतिम रुप देना।

बजट पर कायम रहने और बचत की योजना बनाने से म्यूचुअल फ़ंड, शेयर मार्केट और यहाँ तक कि रियल एस्टेट जैसी योजनाओं में निवेश करने में मदद मिलनी चाहिए। किसी की बचत को फिर से निवेश करना न सिर्फ़ एक सुरक्षित ख़याल है, बल्कि यह ब्याज या लाभांश हासिल करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। जब वित्तीय पोर्टफ़ोलियो बनाने की बात आती है, तो एक कम रेटिंग वाली रणनीति बीमा और टर्म-प्लान को जोड़ना है। जीवनयापन और चिकित्सा उपचार की बढ़ती कीमतों को देखते हुए, किसी की जीवनशैली के अनुरुप एक बीमा समय की ज़रुरत है। बजट बनाना, कर्ज़ चुकाने को प्राथमिकता देना, समान रुप से बचत करना, निवेशों में विविधता लाना और बीमा ख़रीदना, जीवन में उम्र या अवस्था की परवाह किए बिना, बेहतर भविष्य के लिए पैसे बचाने के अहम घटक बने हुए हैं। इन पाँच बुनियादी वित्तीय आदतों को शामिल करने से मिलेनियल, पेशेवरों और सेवानिवृत्त लोगों को एक ठोस वित्तीय नींव बनाने में मदद मिलनी चाहिए। इन्हें आने वाले वर्षों में सभी को ज़्यादा वित्तीय सुरक्षा और समृद्धि का आनंद लेने में भी मदद करनी चाहिए। ●●●

सेलिब्रिटी

यह खास ही रहते हैं आम नहीं!

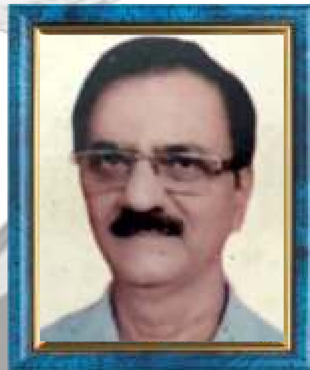

सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव

आरएसएस से प्रेरित होकर कहा जाता है कि राजनीति में अपने राष्ट्रवाद का प्रचार-प्रसार और विस्तार करने के लिए भाजपा ने सेना के रिटायर अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को पार्टी में शामिल किया। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड में भाजपा को इसका खासा लाभ मिला। बीएस खंडूडी जैसे सेना के पूर्व अफसर भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री बने। वहीं मैदानी इलाके उत्तर प्रदेश में पूर्व कर्नल वीके सिंह सैन्य अधिकारी रहे लगातार दोबार 2014 व 2019 में चुनाव जीत कर सांसद बने और केन्द्र में मंत्री भी। हां, इस बार भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं इससे पूर्व देश की राजनीति में विभिन्न दलों की ओर से पूर्व क्रिकेटरों और फिल्मी दुनिया से जुड़े स्टार चुनावों में कहीं चुनाव लड़ते हुए तो कहीं संबंधित पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करते हुए नजर रहे थे। यह भले ही ठीक हो कि राजनीति और ग्लैमर वर्ल्ड का नाता बहुत पुराना हो लेकिन राजनीति में ग्लैमर वलूड से जुडे लोगों की आमद उस वक्त तेज हुई जब अमर सिंह समाजवादी पार्टी में नेता जी मुलायम सिंह यादव के बाद सर्वेसर्वा हुआ करते थे। राज बब्बर, जया प्रदा, और मुजफ्फर अली तक सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। जबकि जया बच्चन राजनीति में आने के साथ ही राज्यसभा में रहीं और आज भी हैं। वहीं दूसरी ओर अटल-आडवानी के युग वाली भाजपा में शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना और हेमा मालनी जैसे फिल्मी कलाकर न सिर्फ भाजपा के टिकट से चुनाव लड़े, बल्कि जीत कर संसद पहुचे और इनमें से तो शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना तो तत्कालीन अटल सरकार में मंत्री भी बने। इधर जब युगों का दौर बदला और अटल और आडवानी के बाद भाजपा मे मोदी और शाह का दौर शुरु हुआ तो भाजपा और उसकी चुनावी राजनीति में ग्लैमर वलूड से जुडे लोग बहुत बड़ी संख्या में जुडे तो वहीं दूसरी ओर इसी के साथ भाजपा की ओर से एक नए ट्रेंड को भी देखने को मिला। जब उसने पूर्व नौकरशाहों को भाजपा से जोड़ कर उन्हें राजनीति के मैदान में उतारा। फिर चाहे वे पूर्व नौकरशाह आरके सिंह हो जो मोदी सरकार में मंत्री बने या फिर एस जयशंकर जो देश के विदेश मंत्री हैं या फिर पूर्व नौकरशाह आरके शर्मा जो योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। लखनऊ के कैंट विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव जीते राजेश्वर सिंह पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। कहा जाता है कि भाजपा ने अपनी राजनीति में नौकरशाहों को जोड़कर उन्हें इसलिए तरजीह दी ताकि उनके माध्यम से शासन प्रशासन में उसका नियंत्रण बना रहे। वहीं अभी पिछले दिनों कलकता हाईकोर्ट के एक जज ने इस्तीफा देकर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया।

बहरहाल, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सेलिब्रिटी खासतौर से ग्लैमर वर्ल्ड से जुडे लोगों को चुनाव के मैदान में उतारने के पीछे संबंधित राजनीतिक दलों का मकसद चुनाव प्रचार में इनके सहारे भीड़ जुटाने का होता है। या कुछ ग्लैमर वर्ल्ड से जुडे लोगों को टिकट देकर उनकी लोकप्रियता के सहारे चुनाव जीतने की मंशा होती है। चुनाव प्रचार में सुपर स्टार से लेकर टीवी के लोकप्रिय सितारों के प्रचार से खूब भीड़ जुटती है। युवाओं में उनको लेकर खासा क्रेज होता है। यही कारण है कि इस बार भाजपा ने बड़ी संख्या में ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़े लोगों को चुनाव के मैदान मे उतारा है। भाजपा ने खुद ही तय किया था कि 75 साल आयु के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो सबसे पहले भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे आडवानी और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रहे डॉ0 मुरली मनोहर जोशी पर लागू हुआ था। लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड का चर्चित चेहरा हेमा मालिनी पर लागू नहीं हुआ। जिन्हें भाजपा ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मथुरा संसदीय सीट से टिकट दिया है। वहीं उनके अतिरिक्त भाजपा की ओर से चुनाव जीतने और मतदाताओं को लुभाने के लिए मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ और रविकिशन जैसे भोजपुरी स्टारों के साथ-साथ कंगना रानौत व बॉलीवुड के "राम" अरुण गोविल को भी टिकट दिया गया है। दक्षिण भारत में भी अपने चुनावी हित साधने के लिए भाजपा ने वहां के भी कई फिल्मी कलाकारों को टिकट दिया है।

जहां तक कंगना का सवाल है तो पिछले काफी समय से जिस तरह से चर्चित और विवादित बयानों के बीच उनके और भाजपा के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं, मोदी सरकार के खास कार्यक्रमों में जिस तरह उन्हें बुलाया जा रहा था। चाहे वह नए संसद भवन का उद्घाटन हो या फिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। जहां कंगना ने बढ़

चढ़ कर हिस्सा लिया। कई मौके पर कंगना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गई प्रशंसा हो या फिर कंगना ने रह-रह कर राजनीति में आने के संकेत दिए हों। उसके बाद यह लग रहा था कि इस बार कंगना को भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव का टिकट मिलना तय है। और अंततः वहीं हुआ जब भाजपा ने कंगना को कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय सीट से टिकट देने का ऐलान किया। वैसे कंगना मूल रुप से इसी पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की ही रहने वाली हैं और पिछले कई सालों से तरह-तरह की फिल्मों मे अलग-अलग तरह का किरदार निभा कर अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। लेकिन कहा जाता है कि वे भाजपा की विचारधारा से प्रभावित हैं। वहीं इधर कंगना को टिकट मिला तो वहीं उधर कांग्रेस नेता और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की कंगना के खिलाफ की गई एक विवादित टिप्पणी ने जहां कंगना को राजनीतिक चर्चा दिला दी, वहीं देखते ही देखते मंडी संसदीय सीट एक हॉट सीट में परिवर्तित हो गई। अब कांग्रेस डेमैज कंन्ट्रोल की नीयत से कंगना में यह कह कर हमला कर रही है कि क्या वह यहां की जनता की समस्या दूर करने के लिए मुंबई से हवाई जहाज पर आएंगी।

अब इस चर्चा का मूल्य विषय यह है कि राजनीतिक दल चाहे वे किसी भी विचारधारा के हों, किसे टिकट दे और किसे न दे। यह उनका अपना विशेषाधिकार होता है। और टिकट देने के पीछे चुनाव जीतना ही मुख्य मकसद होता है। लेकिन वहीं इस सबके विपरीत आमतौर से देखने को यह मिलता है कि सेलिब्रिटी चाहे वे किसी भी क्षेत्र के हों, चुनाव जीत कर जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं लेकिन वास्तव में जमीनी रुप से नहीं जुड़ पाते हैं। न ही संसद में उनकी आवाज बन पाते हैं। क्या कभी देखने को मिला कि किसी सेलिब्रिटी ने संसद में आमजनता के हक में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और उनके लिए चिकित्सा के लिए अपनी आवाज उठाई हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि सेलिब्रिटी और एक आम आदमी के जीवन में बड़ा अंतर होता है। उन्हें अपने जीवन में उन सब चीजों के लिए नहीं जूझना पड़ता है। जिसके लिए आम आदमी अपनी जिन्दगी में रोज अपने और अपने परिवार के लिए संघर्ष करता है। गरीबी और विवशता क्या होती है, वह उसी में जीता है और उसी में मरता है। बस यही रील लाइफ और रीयल लाइफ का अंतर है जिसके कारण सेलिब्रिटी चुनाव जीतने के लिए खास तो होते हैं लेकिन आम जनता के लिए आम नहीं हो पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि इनके पास इतना वक्त ही नहीं होता कि उस कुटिया में झांक कर देखे, जिसके परिवार ने उन्हें अपना कीमती वोट दिया है। बस चुनाव के मौके पर ही बड़ी-बड़ी और हमदर्दी की बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि बस अब इनके चुनाव जीतने के बाद आम आदमी के सारे दुख-दर्द दूर ही हुए। और जबकि सच यह है कि चुनाव खत्म तो तमाम वादे और इरादे भूली बिसरी यादें बन कर रह गए। हां, यहां पर यह कह सकते हैं कि अभिनेता से कांग्रेस के नेता बने सुनील दत्त जरूर एक अपवाद थे जिन्होंने वास्तव में जनता का जनप्रतिनिधि होकर दिखाया। कुछ हद तक आप केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आम जनता का जनप्रतिनिधि कह सकते हैं। जो अमेठी संसदीय सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद वहां के लोगों से जुड़ी रहीं। राज्यसभा का सदस्य होने के कारण केन्द्र में मंत्री तो बन ही चुकी थी, इसलिए अमेठी के लोगों के लिए केन्द्रीय योजनाओं को लागू करने से लेकर समय-समय पर अमेठी उनका आना-जाना बना रहा। जिसका परिणाम यह रहा कि ठीक पांच साल बाद हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां से कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी को चुनाव में हराकर राजनीतिक पंड़ितों को भी हैंरान कर दिया। यहां के लोगों के दुख-दर्द दूर करने के साथ क्षेत्र की हर समस्या का निकारण हो सके, इसके लिए उन्होंने अमेठी में अपना एक घर बनवाया हैं। वहीं कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिन्होंने राजनीति को ही मुंह चिढ़ाने का काम किया। अब जैसे सदी के महानायक कहे जाने वाले बिग बी अमिताभ बच्चन को ही लें 1984 में दिग्गज नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा को इलाबाद से उपचुनाव हरा कर एक नया रिकार्ड बनाया लेकिन राजनीति में ज्यादा दिनों तक बने नहीं रह सके और कुछ कारणों के चलते उनका राजनीति से मोह ही भंग हो गया। इसी तरह धर्मेंद्र को ले भाजपा के टिकट पर चुनाव जीता लेकिन अपने संसदीय सीट से पांच साल तक ऐसा गायब हुए कि उनकी तलाश में क्षेत्र के लोगों ने पोस्टर चस्पा करवा दिए। और तो और उनके बेटे सन्नी देयोल की अगर बात की जाए तो पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट से जीते लेकिन कुछ ही महीनों में उनका भी राजनीति से मोह भंग हो गया। पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी इस मामले में कम नहीं हैं। न भाजपा के ही रह सके और न ही अपनी बेजा हरकतों के चलते कांग्रेस के। कांग्रेस ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया है तो वे आईपीएल मे कमेन्ट्री कर रहे हैं। हां, यह बात अलग है कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत के फिल्मी कलाकारों ने राजनीति में आने के बाद जहां राजनीति की ऊंचाईयों को हासिल किया, तो वहीं दूसरी ओर अपने जनहित के कार्यों से आम जनता के दिलों में ऐसे बसे कि उनके न रहने के बाद भी लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। फिर चाहे वे एमजी रामचंद्र हो, एम. करुणानिधि हो, जय ललिता हो या फिर एनटी रामा राव। क्या कभी अभिनेता से नेता बना कोई नाम उत्तर भारत का भी नाम रोशन करेगा?

●●●

SACTEM का संकल्प

अब हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक से नही होगी कोई मौत

प्रवीण पाठक

स्वास्थ्य सेवाएं भले ही तकनीकि से लैस हो चुकी हैं, लेकिन आज के दौर में भी इमर्जेन्सी सेवाएं व इससे जुड़े नेटवर्क उतने अधिक मजबूत नहीं हुए हैं, जितने होने चाहिए थे। किसी के घर में यदि कोई अचानक बीमार हो जाये या फिर किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो जाये जिससे उसकी जिंदगी पर खतरा मंडरा रहा हो, उस वक्त रोगी के घर वाले अच्छे डॉक्टर्स, अस्पताल या इमर्जेन्सी सेवा के बारे में खोजते है, लेकिन इमर्जेन्सी सेवा के बारे में सही जानकारी व् इलाज के अभाव में रोगी की जान चली जाती है, यदि हम इमर्जेन्सी सेवा के बारे में जागरूक होते तो निश्चित रुप से हम मरीज को घर पर ही इमर्जेन्सी सेवा देकर उसे अस्पताल पहुंचाकर नया जीवनदान दे सकते थे, लेकिन ऐसा अधिकतर केसेस में नहीं हो पाता है।

सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। सब कुछ है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है। जिसकी वजह से सरकारी अस्पतालों की तरफ कोई भी जल्दी से रुख नहीं करना चाहता है। ऐसे में इमर्जेसी सेवा के दौरान हम ऐसा क्या करें जिससे मरीज को घर पर आराम मिल जाए और हम समय रहते अस्पताल में मेडिकल एक्सपर्ट की निगरानी में इलाज जारी रख सकें। इसके लिए जागरुकता सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। इमर्जेन्सी सेवा की सही जानकारी और सही ट्रीटमेंट ही इसका बचाव है। इस बड़ी और गंभीर समस्या से निपटने के लिए सेक्टम के फाउंडर इमर्जेन्सी मेडिकल एवं ट्रॉमा के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर लोकेन्द्र गुप्ता ने संकल्प लिया है कि वह सेक्टम सोसाइटी के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में वर्कशॉप, मीडिया, सरकारी तंत्र , वेबसाइट, मोबाइल ऐप और इमर्जेन्सी सेवा पर आधारित बुक्स के माध्यम से लोगों को इमर्जेन्सी से निपटने के लिए जागरूक करेंगे ताकि किसी भी मरीज की हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या अन्य किसी इमर्जेन्सी स्थिति में मौत न हो सके. डॉक्टर गुप्ता के मुताविक अगर उत्तर प्रदेश सरकार सेक्टम का साथ देगी तो निश्चित रुप से वह इमर्जेन्सी चिकित्सा सेवा में एक क्रांतिकारी बदलाव लाकर लोगो की जान बचाने मे कामयाब होंगे।

डॉक्टर लोकेन्द्र गुप्ता ने इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए "सेक्टम सोसाइटी" का गठन किया है, जिसमे इमर्जेन्सी मेडिकल से जुड़े 100 एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम तैयार की है, इस सोसाइटी में निजी और सरकारी अस्पतालों के इमर्जेन्सी मेडिकल हेड शामिल है। जो विभिन्न चिकित्स्कीय क्षेत्र में दक्ष है।

डॉ. गुप्ता एडवांस कार्डिएक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, फंडामेंटल क्रिटिकल केयर सपोर्ट, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, क्रिटिकल केयर मेडिसिन बोर्ड रिव्यू और एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड लाइफ सपोर्ट सहित कई लाइफ सपोर्ट की सेक्टम सोसाइटी बनाकर लोगों तक इमरजेंसी सेवाओँ को पहुंचाने का कार्य कर रहें।

इस बारे में डॉ0 लोकेन्द्र गुप्ता ने लखनऊ जंक्शन (समाचार पत्रिका) से विस्तृत बातचीत की जिसके प्रमुख अंश पाठकों के साथ साझा कर रहा हूँ।

डॉक्टर

साहब, सेक्टम सोसाइटी के गठन का विचार कब और क्यों आया?

डॉक्टर - मेरा इमरजेंसी सेवाओं के क्षेत्र में लंबा अनुभव है, दिन रात मरीजों की सेवा करते करते इस क्षेत्र में आ रही समस्यायों को नजदीकी से देख रहा हूँ, समाज में बड़ा तबका ऐसा है जिनकी महंगे अस्पतालों तक पहुँच नहीं है, और सरकारी अस्पतालों में संसाधन होने के वाबजूद काम करने की ललक और सेवा भावना नहीं है। इसी को देखते हुए मैंने सेक्टम सोसाइटी बनाई है। इस सोसाइटी के माध्यम से सभी छोटे और बड़े अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इमरजेंसी सेवा सभी तक पहुंचे इसके लिए प्रयास जारी है। रैबीज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में कौन सा टीका कब लगे इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं।

अभी तक इस मुहीम में कितने अस्पताल सूचीबद्ध हुए है?

डॉक्टर- अभी तक लखनऊ के अस्पताल - एरा, पीजीआई, कानपुर, बरेली, फरीदाबाद ग्रेटर नोएडा के बड़े - छोटे अस्पताल के डॉक्टर को जोड़ रहा हूँ। धीरे धीरे इमर्जेंसी मेडिकल से जुड़े डॉक्टर्स के काल मेरे आपस आ रहे है, निश्चित रूप से इसी साल के अंत तक एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में कामयाब होंगे।

सेक्टम सोसाइटी को बढ़ाने के लिए सरकारी तंत्र से आपको किसी तरह की कोई मदद मिल रही है या नहीं?

डॉक्टर- हां ! मैंने कई डिपार्टमेंट से संपर्क किया है लेकिन उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन हम लगातार गवर्मेंट सेक्टर को जोड़ने के लिए प्रयाश कर रहे हैं। जैसे रेलवे, पुलिस विभाग, फारेस्ट विभाग, आंगनबाड़ी, स्वास्थय विभाग, आपदा विभाग। सरकारी डिपार्टमेंट जो जोड़ने के साथ स्कूली बच्चों को जागरूक करने का कार्य चल रहा है। वही जल्द ही इमरजेंसी सेवाओं को लेकर एक पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी जो लोगों को इमरजेंसी सेवाओं के बारे में जागरुक करेगी।

डॉक्टर साहब ! इस समय युवाओं, बच्चों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे है, इससे कैसे निपटें?

हां। इस समय समाज में हार्ट अटैक के मामले बहुत बढ़ रहे है। खासकर युवाओं और बच्चों में। युवा और बच्चे लगातार पश्चिमी संस्कृति का खानपान कर अपने दिल को कमजोर कर रहे है।

सभी से अपील करता हूँ कि प्रकृति के साथ मिलकर अपनी जीवनशैली को बेहतर बनाएं और मिलेटस को अपने खानपान में सम्मिलित करें, योग करें, सुबह शाम पैदल चलें।

अगर किसी को अचानक चेस्ट पैन हो तो क्या करें?

डॉक्टर- ऐसी स्थिति में मरीज को Aspirin 350mg की टैबलेट पानी में घोलकर पिलाएं और आराम करने दें। ऐसे मरीज को sorbitarte 5/10 mg की टैबलेट डाक्टर की सलाह पर ही देना चाहिए क्योंकि ये हार्ट अटैक के कुछ केसेस मे बीपी कम कर सकता है। आराम होने पर अच्छे चिकित्सक से चेकअप कराएं ताकि मर्ज पकड़ में आ सके और बेहतर इलाज हो सके।

सेक्टम सोसाइटी की आगे की कार्ययोजना क्या है?

डॉक्टर- सेक्टम लगातार इस दिशा की ओर काम कर रहा है। 11 मई को पदमश्री उमेश भारती जी लखनऊ में रेबीज को लेकर एक कार्यशाला आयोजित करेंगे। इसी साल के अंत दिसम्बर महीने में पूरे उत्तर प्रदेश के इमर्जेन्सी मेडिकल एक्सपर्ट्स का एक सम्मलेन आयोजित किया जायेगा जिसमे सभी इस एक्सपर्ट्स स्वास्थय के क्षेत्र में सेक्टम का जागरुकता सन्देश हर घर में कैसे पहुंचाया जाये, इस पर बात कर उत्तर प्रदेश सरकार से इस नेक काम में भागेदारी निभाने के लिए अनुरोध करेंगे, ताकि कोई भी आदमी आगे से कि हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक आदि से न मरे। ये तभी संभव होगा जब हम इमर्जेन्सी सेवा को मॉडर्न इमर्जेन्सी सेवा के रूप में लोगो तक जागरुकता के माध्यम से अपनी बात पहुचायेंगे। ●●●

विश्व स्वास्थ्य दिवस (07 अप्रैल) के मौके पर पाठकों के लिए कुछ हेल्थ टिप्स

डॉक्टर- अगर आप को हमेशा स्वस्थ्य रहना है तो अपनी जीवन शैली को प्रकृति के साथ जोड कर चलें। कुछ जरूरी हेल्थ टिप्स आप के साथ साझा कर रहा हूँ।

- संतुलित आहार सबसे अहम है- हर तरह की चीजें खाएं, सही मात्रा में खाएं।
- डायट में विविधता लाएं- अलग-अलग तरह की और अलग-अलग रंगों के फल-सब्जियां, सीड्स आदि खाएं।
- जहरीले ट्रांस फैट को खत्म करें - तला हुआ और पूरी तरह तला हुआ खाने से बचें।
- नमक, चीनी और सैचुरेटेड ट्रांस-फैट की खपत कम करें
- सूक्ष्म-पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए फोर्टिफाइड फूड खाएं।
- किसी भी समय का खाना न छोड़ें - कम और जल्दी-जल्दी खाने की आदत रखें, समय पर खाएं,
- पैकेटबंद, सुरक्षित किया गया, प्रसंस्कृत किया गया, बेकरी, मैदा, तला हुआ और कैन वाला खाना न खाएं, बाहर का और देर रात खाना न खाएं।
- एल्कोहॉल, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन न करें।
- खूब पानी पिएं और स्थानीय स्तर पर पैदा की जाने वाली चीजें खाएं, प्राकृतिक चीजें खाएं।
- समुचित खान-पान इस बात का सूचक होता है कि आप खुद का कितना सम्मान करते हैं, और यह न भूलें कि सेहत ही एकमात्र ऐसी संपत्ति है जो हमेशा आपका साथ देगी।

कांग्रेस करेगी करिश्मा या चलेगा मोदी मैजिक

लोस 2024: दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा चुनाव 7 फेज़ में 97 करोड़ वोटर डालेंगे वोट

मुस्ताअली बोहरा

18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक होना है। यह दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा या यूं कहा जाए कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल सात चरणों में होगा। चुनाव आयोग 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर चुका है। पहला चरण 19 अप्रैल 2024 को होना है जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल 2024 को होना है, जिसमें 12 राज्य के 88 सीटों पर मतदान होगा। वहीं तीसरा चरण 07 मई 2024 को होना है जिसमें 13 राज्य के 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई 2024 को होना है जिसमें 10 राज्य के 96 सीटों पर मतदान होगा। पांचवे चरण में 20 मई 2024 को होना है, जिसमें 8 राज्य के 49 सीटों पर मतदान होगा, जबकि छटवें चरण में 25 मई 2024 को होना है, जिसमें 7 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा। अंतिम और सातवे चरण में 01 जून 2024 को होना है, जिसमें 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा। मतगणना 4 जून 2024 को होगी। मालूम हो कि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव के बाद कुल 543 सांसद चुनकर आएंगे। पिछली बार 2019 में हुए आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती थीं और अपने पूर्ण बहुमत को बरकरार रखा था। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती थीं। इस बार भाजपा एनडीए गठबंधन ने 400 पार का नारा दिया है। जबकि अकेले भाजपा 370 पार जीतने का दावा कर रही है।

चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इन पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार हैं। इस बार का आम चुनाव देश की दशा और दिशा तय करेगा। पीएम नरेन्द्र मोदी सत्ता की हैट्रिक लगाकर पंडित जवाहरलाल नेहरु के रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रचना चाहते हैं तो कांग्रेस इस बार छत्रपों के सहारे भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश कर रही है।

2024 में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के करीब 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के साथ ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जबकि साल के आखिर में तीन राज्यों में चुनाव हैं। पूर्वोत्तर में ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, तो दक्षिण के आंध्र प्रदेश और पश्चिमी भारत के महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे। हरियाणा और झारखंड में भी चुनाव हैं। लोकसभा और इन राज्यों के चुनाव देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम हैं।

यहां ये बताना लाजमी होगा कि इससे पहले 17वीं लोकसभा के गठन के लिए भारत में 11 अप्रैल, 2019 से 19 मई, 2019 के बीच सात चरणों में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में तीन बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में सभी सात चरणों में मतदान कराए गए थे। 2019 में चुनावी नतीजे 23 मई को घोषित किए गए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने कुल 353 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी ने अकेले ही 303 सीटें हासिल की थीं, जबकि कांग्रेस को 52 सीटें मिली थीं। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन को 92 सीटें हासिल हुई थीं।

संविधान के अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा का चुनाव प्रत्येक पाँच साल में होना चाहिए। संविधान के अनुसार लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। फिलहाल लोकसभा सीटों की संख्या 545 है, जिनमें से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 543 सीटों के लिए आम चुनाव होते हैं। कुल सीटों में से 131 लोकसभा सीटें रिजर्व होती हैं। इन 131 में अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें रिजर्व हैं। यानी इन सीटों पर कोई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए होती हैं। अगर बहुमत से कुछ सीटें कम भी पड़ जाएं तो दूसरे दलों के साथ गठबंधन करके भी सरकार बनाई जा सकती है। राजनीतिक दलों का गठबंधन चुनाव से पहले भी हो सकता है और नतीजों के बाद भी। लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद लेने के लिए विपक्षी पार्टी के पास कम से कम कुल सीटों की 10 फीसदी संख्या होनी चाहिए यानी 55 सीटें।

2014 के आम चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें ही मिल पाई थीं। 2019 में भी कांग्रेस 55 सीटें हासिल नहीं कर सकी थीं।

कांग्रेस को करिश्में का इंतेजार, चलेगा मोदी मैजिक

2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कांग्रेस दो आम चुनाव बुरी तरह हार चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। 2024 का चुनावी मुकाबला बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच है। लेकिन कई विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं। ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर होगी तो कुछेक सीटों पर ये मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। पीएम मोदी के अगुवाई में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करना चाहती है। साल 2014 और 2019 से लगातार दो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की और 2024 में हैट्रिक लगाकर इतिहास रचने की कोशिश में है। लगातार तीन बार लोकसभा चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अभी जवाहरलाल नेहरू के नाम दर्ज है और यदि इस बार भाजपानीत सरकार बनी तो नरेन्द्र मोदी तीसरी बार पीएम बनकर इस रिकार्ड की बराबरी कर लेंगे। खैर होगा क्या ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा।

लोकसभा चुनाव के साथ ही चार राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। फिलहाल आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआर की सरकार है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। ओडिशा में काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजू जनता दल सरकार है, जबकि सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा वाली पार्टी शासन कर रही है और इसके मुखिया प्रेम सिंह तमांग हैं। इस तरह से इन चार राज्यों में अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दें बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दलों का कब्जा है। इस बार भी क्षेत्रीय दलों के बीच मुकाबला होने की संभावना है और कांग्रेस, भाजपा दोनों ही इन राज्यों में खुद को स्थापित करने की कोशिश में लगीं हैं। भारतीय जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी ओडिशा की चुनावी राजनीति में किस्मत आजमाती रही है, लेकिन उसे कभी भी सत्ता का स्वाद चखने का मौका नहीं मिल सका है। 2000 के विधानसभा चुनाव में बीजेडी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में पूर्ण बहुमत हासिल किया था और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद दोनों का गठबंधन टूट गया, लेकिन नवीन पटनायक का दबदबा बरकरार रहा। कांग्रेस लंबे समय से सत्ता बाहर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बीजेडी को कांटे की टक्कर दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में मुकाबला नहीं कर सकी। इस बार बीजेडी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां पूरे दमखम के साथ मैदान में है। इसी तरह अरुणाचल की राजनीति में बीजेपी का दबदबा है। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम में राज्य की सियासी हालत बदल चुकी है। सिक्किम की राजनीति से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बाहर हो गए हैं। 35 सीटों वाली विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी एसडीएफ का दबदबा है। कांग्रेस और बीजेपी यहां अपना खाता भी नहीं खोल पाई थीं। इस बार भी सिक्किम में एसडीएफ को अपनी वापसी की उम्मीद दिख रही है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपना खाता खोलने के लिए बेताब हैं। अरुणाचल में देखना है कि बीजेपी अपना वर्चस्व रख पाती है या फिर कांग्रेस की वापसी होगी ?

विधानसभा चुनाव में भी होगी अग्नि परीक्षा

साल के शुरु में चार राज्यों में तो अंत में तीन राज्यों में हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव होने हैं। कांग्रेस हरियाणा में अपनी वापसी के लिए हरसंभव कोशिश में जुटी है, लेकिन पार्टी की गुटबाजी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सत्ता और विपक्षी दोनों गठबंधनों की परीक्षा होगी। यह विधानसभा चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पिछली बार जो एक साथ थे, वो अबकी बार एक-दूसरे के खिलाफ हैं। शिवसेना और एनसीपी में टूट के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव होगा, जिसमें तमाम गुटों की अग्नि परीक्षा होगी। महाराष्ट्र की सत्ता पर मौजूदा समय में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी काबिज है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ लेकर महाराष्ट्र की सत्ता जरुर हासिल कर ली है, लेकिन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी एक साथ हैं, इस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव इन सभी पार्टियों के लिए मायने रखता है। झारखंड में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूबे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने का आसार नजर आ रहे हैं। एनडीए में बीजेपी और आजसू साथ हैं, तो महागठबंधन में हेमंत सोरेन की जेएमएम, कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी हैं। इस तरह हेमंत सोरेन के सामने सत्ता बचाने की चुनौती होगी। फिलहाल यहां महागठबंधन सत्ता में है और अपना कब्जा जमाए रखने की कोशिश करेगा, तो बीजेपी अपनी वापसी के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी की पार्टी में घर वापसी कराकर उन्हीं को अपना अगुवा बना रखी है, ताकि आदिवासी वोटों को साधे रखा जा सके।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 370 से जुड़े मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा के चुनाव कराने का आदेश दिया था। जम्मू-कश्मीर के सीटों का परिसीमन भी हो चुका है। माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर-अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर साल 2024 में कुल 8 राज्यों में चुनाव होंगे। साल 2024 में आठ राज्यों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के चुनाव होते हैं तो अपने आप में ऐतिहासिक होंगे।

2024 में देश के जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रीय दलों का दबदबा है, तो कुछ राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। अरुणाचल, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में बीजेपी

के दम पर एकनाथ शिंदे सरकार चला रहे हैं, ओडिशा में नवीन पटनायक के नेतृत्व में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व में वाईएसआर कांग्रेस काबिज है तो झारखंड में जेएमएम के साथ कांग्रेस सत्ता में हिस्सेदार है। सिक्किम में एसडीएफ का साढ़े तीन दशक से दबदबा है। इस तरह बीजेपी और क्षेत्रीय दलों के बीच भी चुनाव हैं। कांग्रेस के लिए अपने सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती है। क्षेत्रीय दलों के साथ भी सियासी संकट कम नहीं है।

चार राज्यों में होंगे विधानसभा चुनाव

लोकसभा चुनाव के साथ चार राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ओडिशा में चार चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे. यहां 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 20 मार्च 2024 को जारी होगी और मतदान 19 अप्रैल 2024 को होगा. राज्य की 60 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। सिक्किम विधानसभा के लिए भी एक ही चरण में सभी 32 सीटों पर वोट डाले जाएंगे. नोटिफिकेशन की तारीख 20 मार्च और वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों पर चुनाव के लिए 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा, अलग-अलग राज्यों की 26 विधानसभा सीटों पर उप चुनाव भी होंगे। ये चुनाव भी आम चुनावों के साथ होंगे। बाद में चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनावों की मतगणना की तारीख को बदलकर 2 जून 2024 करने की घोषणा की है। दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 2 जून को ही खत्म हो रहा है। ऐसे में मतगणना भी दो जून तक पूरी करना अनिवार्य है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती की तारीख में बदलाव किया है। दोनों राज्यों में मतदान 19 अप्रैल को होना है। इससे पहले शनिवार को चुनाव आयोग ने कहा था कि मतगणना 4 जून को होगी। दोनों राज्यों में लोकसभा चुनावों को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है।

तीन राज्यों में सात चरणों में चुनाव

सिर्फ तीन ऐसे राज्य हैं, जहां सात चरणों में चुनाव होने हैं। ये राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 80 सीटें हैं, बिहार में 40, पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं।

आम चुनाव: एक नज़र में

लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत वोटर हैं। इनमें 47.1 करोड़ महिलाएं, 49.7 करोड़ पुरुष और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इनमें 1.89 करोड़ पहली बार वोटर्स हैं और 19.74 करोड़ युवा वोटर्स, जिनकी उम्र 20 से 29 साल की है। इसके अलावा 01 जनवरी 2024 को जिनकी उम्र 18 साल नहीं हुई थी, उनका भी नाम जोड़ा गया है। इसमें 13.4 लाख ऐसे आवेदन है, जो 1 अप्रैल 2024 तक 18 साल के हो जाएंगे और वोट दे सकेंगे। इसमें 88.4 लाख दिव्यांग, 82 लाख 85 साल से अधिक की उम्र के और 48 हजार ट्रांसजेंटर शामिल हैं। 85 साल से अधिक की उम्र के लोगों के लिए घर से वोट करने की सुविधा की गई है। इसके लिए मतदान कर्मी उनके घर पर जाकर उनका वोट रिकॉर्ड करेंगे। 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा।

22 राज्यों में एक चरण में मतदान - अरुणाचल प्रदेश, अंडमान

निकोबार द्वीप समूह , आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, लद्दाख, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड.

4 राज्यों में 2 चरणों में चुनाव - कर्नाटक, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर.

2 राज्यों में 3 चरण में मतदान - छत्तीसगढ़ और असम

3 राज्यों में 4 चरणों में चुनाव - ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड.

2 राज्यों में 5 चरणों में चुनाव - महाराष्ट्र और जम्मू और कश्मीर

3 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव - उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार.

पहला चरण (21 राज्यों की 102 सीटों के लिए चुनाव होगा)

20 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन

19 अप्रैल को मतदान होगा।

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी की कुल 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

दूसरा चरण (13 राज्यों की 89 सीटों के लिए चुनाव होगा)

28 मार्च को गजेट नोटिफिकेशन

26 अप्रैल को मतदान होगा।

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होगा.

तीसरा चरण (12 राज्यों की 94 सीटों के लिए चुनाव होगा)

12 अप्रैल को गजेट नोटिफिकेशन

07 मई को मतदान होगा।

असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नागर हवेली और दमन दीव की कुल 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.

चैथा चरण (10 राज्यों की 96 सीटों के लिए चुनाव होगा)

18 अप्रैल को गजेट नोटिफिकेशन

13 मई को मतदान होगा।

आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे.

पांचवा चरण (8 राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा)

26 अप्रैल को गजेट नोटिफिकेशन

20 मई को मतदान होगा.

छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख की 49 सीटों पर मतदान होगा.

छठा चरण (7 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा)

29 अप्रैल गजेट नोटिफिकेशन

25 मई को मतदान होगा।

बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा.

सातवां चरण (8 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव होगा)

07 मई को गजेट नोटिफिकेशन

01 जून को मतदान होगा.

बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ की कुल 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे।

चार चरण में होंगे मध्यप्रदेश में चुनाव

पहला चरण - 19 अप्रेल

सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा

दूसरा चरण- 26 अप्रेल

टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल

तीसरा चरण- 7 मई

मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़

चैथा चरण- 13 मई

देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा

भाजपा की नज़र सभी 29 सीटों पर

मध्यप्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर घमासान होने वाला है। 29 सीटों में से एक सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि 28 सीटें भाजपा के पास है। भाजपा की नज़र अब सभी 29 सीटें जीतने पर है। इधर कांग्रेस ने भी पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की चुनावी सभाओं और रैलियों का कार्यक्रम भी तैयार किया गया है।

मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच

इस चुनाव में छह राष्ट्रीय पार्टियाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी (उत्तर पूर्व में पीए संगमा की बनाई पार्टी, जो राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस हासिल करने वाली उत्तर पूर्व की पहली पार्टी है) और आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में हैं। लेकिन यह चुनाव मुख्य तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ तीसरी बार चुनावी समर में है। इंडिया गठबंधन की ओर से किसी चेहरे पर अब तक आम राय नहीं बनी है। राष्ट्रीय पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर सभी दल किसी ना किसी गठबंधन का हिस्सा हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए में पीए संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी, जयंत चैधरी के राष्ट्रीय लोकदल और एचडी देवगौड़ा के जनता दल (एस) सहित कई छोटे बड़े दल शामिल हैं। जबकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा वामपंथी दल, लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, स्टालिन की डीएमके, हेमंत सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा, उद्धव ठाकरे गुट है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, सुश्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल भी चुनावी मैदान में है। ●●●

पुष्कर सिंह धामी सरकार के निराशाजनक 2 साल!

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा की माने तो इन दो वर्षो के कार्यकाल में राज्य की धामी सरकार की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, जिस पर राज्यवासियों को गर्व हो सके। उनका मानना है कि भाजपा सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में केवल महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों का उत्पीड़न करने, जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने तथा मंहगाई, भ्रष्टाचार व बरोजगारी बढ़ाने के अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं किया है,जिसपर गर्व किया जा सके। हम आंकलन करे तो भाजपा सरकार के दो वर्ष के कार्यकाल में उत्तराखंड में हत्या, चोरी, डकैती, मासूमों से बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है।जिनमे अंकिता भण्डारी जघन्य हत्याकाण्ड, हेमा नेगी हत्याकाण्ड, पिंकी हत्याकाण्ड, जगदीश चन्द हत्याकाण्ड, विजय वात्सल्य हत्याकाण्ड, केदार भण्डारी तथा विपिन रावत हत्याकाण्ड जहां शामिल है। वही राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग से बलात्कार की घटना से गिरती कानून व्यवस्था उजागर हो गई है,जो राज्य की अस्मिता पर चोट भी है।साथ ही राज्य सरकार के कई विभागों में हुए भर्ती घोटालों और व्याप्त भ्रष्टाचार से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा सरकार इन दो वर्षो के कार्यकाल में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही है और उसका भयमुक्त समाज-भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा ध्वस्त होकर रह गया है।

चाहे वह अंकिता भण्डारी हत्याकांड हो, हेमा नेगी हत्याकांड हो, पिंकी हत्याकांड, जगदीश चन्द हत्याकांड, विजय वात्सल्य हत्याकाण्ड, केदार भण्डारी तथा विपिन रावत हत्याकाण्ड हो,इन सारे जघन्य हत्याकाण्डों में सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप भी विपक्ष द्वारा लगाए जाते रहे है। वही चर्चित अंकिता भण्डारी हत्याकांड में शामिल वीआईपी का नाम धामी सरकार अभी तक उजागर नहीं कर पाई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घोटाला, लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, फारेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, सहकारिता भर्ती घोटाला, पटवारी भर्ती घोटालो में हुई कई गिरफ्तारियां जिनमें अधिकतर भाजपा नेता संलिप्त थे ,से भाजपा सरकार का चेहरा उजागर हुआ है।जिसके चलते राज्य की धामी सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के आरोपो से घिरती रही है।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष एस.राजू द्वारा अपने त्यागपत्र में आरोपित घोटाले मे लिप्त सफेदपोश नेता कौन है, इस पर भाजपा सरकार आज तक मौन साधे हुए है। भर्ती घोटालों में आरोपित हाकम सिंह सत्तारुढ़ पार्टी के पदाधिकारी है और हरिद्वार के संजय धारीवाल तथा नितिन चौहान मण्डल अध्यक्ष व महामंत्री हैं इससे स्पष्ट है कि दो साल के कार्यकाल में सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार का उद्योग बड़ी तेजी से फलता-फूलता रहा है।उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारों की संख्या में रोज इजाफा हो रहा है । रोजगार मांगने पर सरकार द्वारा बेरोजगारों पर निर्मम लाठी चार्ज किये गए। प्रदेशभर में निर्माण सम्बन्धी कार्यों में खुलेआम कमीशनखोरी, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी तथा छोटे ठेकेदारों का शोषण आम बात हो गई है। मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण की बाबत सरकार कोई नीति नहीं बना पाई है। प्रदेश में स्थापित लघु व बड़े उद्योग लगातार बंद होते जा रहे है या फिर इन उद्योगों का पलायन हो रहा है,जिसे रोकने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। इन दो वर्षों में राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरी तरह ध्वस्त हो गई ।

उत्तराखंड में जोशीमठ त्रासदी के प्रभावित परिवार सरकार से विस्थापन की मांग करते रहे परन्तु राज्य की धामी सरकार आपदा पीडितों के विस्थापन तथा पुर्ननिर्माण के लिए ठोस निर्णय लेने में विफल साबित हुई है।

प्रदेश में शराब माफिया और खनन माफिया हावी है। सरकारी संरक्षण में शराब की तस्करी तथा खनन में हो रहे भ्रष्टाचार के कारण सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि हो रही है। वही गन्ना किसानों का पिछला बकाया भुगतान सरकार नहीं कर पाई है,जबकि नई गन्ना फसल के समर्थन मूल्य में मात्र 20 रुपये की वृद्धि किसानों का शोषण जैसा ही है। पानी, बिजली के दामों में

लगातार बढ़ोतरी कर आम आदमी पर लगातार महंगाई का बोझ डाला गया है।
लेकिन अपनी विफलताओं पर पश्चाताप करने की बजाय राज्य की धामी सरकार झूठी उपलब्धियों के जरिए आमजनता को गुमराह करने में लगी हुई है।
भाजपा सरकार किसानों की आय सन 2022 तक दोगुनी करने के दावे कर रही थी, लेकिन किसानों की दोगुनी आए आज तक भी नहीं हो सकी है, उत्तराखंड के हालात यह है की शराब सस्ती है और डीजल, खाद और बिजली-पानी का बिल, सभी महंगी हो गया हैं। प्रदेश में किसान भी पूरी तरह से खुद को असहाय महसूस कर रहा है। सरकार ने इस बार गन्ने का समर्थन मूल्य भी नाम मात्र को बढ़ाया, जिससे गन्ना किसानों को भी काफी दिक्कतें हो रहीं हैं। राज्य सरकार सिर्फ हवा हवाई बातें करके अपने दो साल के कार्यकाल को सफल बता रही है, जबकि राज्य में माहौल निराशा भरा है। तभी तो कभी धर्म के नाम पर कभी मंदिर के नाम पर लोगो को बहकाने की कौशिश की जाती है।भाजपा अपनी सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए भावनात्मक मुद्दों को आगे बढ़ाकर आमजन को गुमराह कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्यों की सरकार अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए बार-बार समान नागरिक संहिता की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून को समान नागरिक संहिता कहना सही नहीं है क्योंकि इसका दायरा केवल उत्तराखंड राज्य तक सीमित होगा। एक संहिता जिसके लागू होने का दायरा एक राज्य तक सीमित होगा, उसे यूनीफॉर्म कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं से बाहर यूसीसी का कोई अर्थ ही नहीं है। भाजपा यूसीसी का इस्तेमाल महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के नीचे दबी जनता का ध्यान हटाने के लिए कर रही है। जबकि विकास के मुद्दे कही दबकर रह गए है। जबकि धामी सरकार का दावा है कि बीते 24 महीने में 48 बड़ी गारंटियों को धामी सरकार ने यथार्थ में परिवर्तित किया है। ये वह तमाम संकल्प थे, जिनका वादा 2022 विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं भाजपा ने जनता से किया था। लेकिन ये गारंटी और संकल्प कौन से है, यह बताने की कौशिश नही की गई। वही नुजूल नीति लागू न कर पाने के कारण हल्द्वानी में हजारों घरों पर जहां बुलडोजर चलाकर लोगो को बेघर कर दिया गया, वही गुस्साए लोगों के उपद्रव के कारण कानून व्यवस्था तक प्रभावित हुई है। आज भी राज्य में नुजूल की हजारों एकड़ भूमि है, जिसपर ठोस नीतिगत पहल करने की जरूरत है, न कि बुलडोजर चलाकर लोगो को फुटपाथ पर लाकर छोड़ देने की। जो राज्य सरकार की विफलता में ही गिना जाएगा। इसलिए हम कह सकते है कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी भाजपा सरकार के दो वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा धामी सरकार की तथाकथित उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है,परन्तु वास्तविकता यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार इन दो वर्षों में ज्यादातर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। जिस कारण आमजन निराश हुआ है। ●●●

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

कुत्ता उनका गटर में न गिरता, सीवर की जल्दी सफ़ाई न होती

पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित

भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन लखनऊ अंचल द्वारा बैंक के मुख्य शाखा परिसर में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि स्टेट बैंक लखनऊ मंडल के मुख्य महाप्रबन्धक शरद एस. चांडक के साथ लखनऊ अंचल के उपमहाप्रबंधक आर. नटराजन तथा स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन के महामंत्री अतुल स्वरूप व मंडल अध्यक्ष दिनेश चन्द्रा एवं के.के.सिंह पूर्व महामंत्री ने दीप प्रज्जवलित कर कवि सम्मेलन का शुभारम्भ किया।
प्रारम्भ में बलिया से आये गीतकार महेश चन्द्र गुप्त 'महेश' ने अपनी रचना- "किया है तुमने मुझको तंग, पिलाकर ठंढाई में भंग। सुर्ख होने लगे मेरे गाल, ए रसिया मल दो आज गुलाल।।" से दर्शकों को सराबोर कर दिया।
प्रसिद्व व्यंगकार श्यामल मजूमदार ने कवि सम्मेलन का संचालन करते हुये व्यंग्य परोसा- "सियासत में अंधी कमाई न होती, तो चेहरे पे उनके लुनाई ना होती। अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता, सीवर की जल्दी सफ़ाई न होती।।" इस प्रस्तुति ने दर्शकों की तालियां बटोरी।
इनके बाद राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाने वाली कवयित्री शशि श्रेया की रचना- "शयन रत मन जगाना आ गया है, विजय का पथ बनाना आ गया है। हवा के रूख की अब चिंता नही है, मुझे दीपक जलाना आ गया है।।" को दर्शकों ने बहुत पसन्द किया। इनके अतिरिक्त बाराबंकी के हास्य कवि, संदीप अनुरागी व अन्य कवियों ने अपनी रचनायें प्रस्तुत की जिन्हें लोगों ने सराहा। अंत में अंचल अध्यक्ष संजीव अग्रवाल ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया।

शौर्य

उत्तराखंड के भूले बिसरे वीर योद्धा पुरिया के योगदान की कहानी

उत्तराखंड के गढ़वाल के मध्ययुगीन नरेशों के इतिहास में विलक्षण प्रतिभा के धनी पुरिया नैथानी का नाम एक कुशल-चतुर कूटनीतिज्ञ और सेनापति के रुप में याद किया जाता है। जिन्होंने वाकचातुर्य से न केवल गढ़वाल राज्य की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाया बल्कि अपनी क्रूरता के लिये जाने वाले औरंगजेब से गढ़वाल पर लगे जजिया कर तक माफ करवाया दिया था। उनकी मेधा व हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रयासों से औरंगजेब इतना प्रसन्न हुआ है कि उसने गढ़वाल के लोगों पर लगे जजिया कर माफ करने की घोषणा कर दी। विलक्षण प्रतिभा के धनी पूर्णमल उर्फ पुरिया नैथानी का जन्म शुक्ल पक्ष पूर्णमासी भाद्रपद यानी अगस्त 1648 ई को पौड़ी जनपद के ग्राम नैथाणा में गौडु नैथाणी के घर हुआ। तत्कालीन गढ़ नरेश पृथ्वी शाह के करीबी मंत्री डोभाल, जो एक प्रसिद्ध ज्योतिषज्ञ भी थे, ने पुरिया जी की जन्मपत्री देखकर उनके असाधारण उज्ज्वल भविष्य को दर्शाते ग्रहों को पहचाना। पुत्रहीन डोभाल ने पुरिया जी के पिता से उन्हें अपने कन्या के वर के रुप में मांग लिया था। साथ ही उनके पिता के भरण-पोषण के लिये मासिक पेंशन की व्यवस्था भी की। इस तरह कुशाग्र बुद्धि के मेधावी पुरिया की शिक्षा-दीक्षा राजकुमारों के साथ हुई। राजगुरु के सानिध्य में उन्होंने संस्कृत, इतिहास,भुगोल, अस्त्र-शस्त्र, धर्मशास्त्रों व घुड़सवारी की शिक्षा हासिल की। कालांतर मंत्री डोभाल की पुत्री से उनका विवाह हुआ।

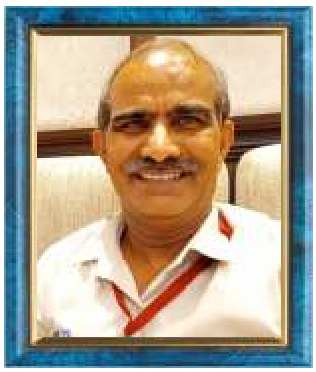

डॉ श्रीगोपाल नारसन

एडवोकेट

वीर पुरिया वर्ष 1668 में गढ़वाल नरेश पृथ्वीपति शाह के प्रतिनिधि के रूप में औरंगजेब की बेटी रोशनआरा के विवाहोत्सव में भाग लेने गये। उन्होंने अपनी प्रतिभा से औरंगजेब को प्रभावित किया। एक छत्रप से कोटद्वार के भावर इलाके के एक बड़े भूभाग को औरंगजेब के निर्देश पर मुक्त कराया, जिसके लिए गढ़ नरेश से सैकड़ो बीघा जमीन पुरिया जी को प्रदान की। वहीं वर्ष 1680 में औरंगजेब के दरबार में अपने वाकचातुर्य से आर्थिक रुप से कमजोर गढ़वाल की जनता को जजिया कर से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली। पुरिया जी के सांप्रदायिक सद्भाव के तर्कों से औरंगजेब इतना प्रभावित हुआ कि उसने गढनरेशों की प्राचीन राजधानी देवलगढ़ में प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की। इस ऐतिहासिक सफल यात्रा के बाद गढ़वाल नरेश ने उन्हें अपना सेनापति बना दिया। उन्होंने गढ़वाल की सीमाओं को अक्षुण्ण बनाने के लिये कई युद्धों में वीरतापूर्वक निर्णायक भूमिका निभाई और कई विद्रोहों व हमलों में राजवंश की रक्षा की।

कालांतर, गोरखा युद्ध व अंग्रेजों के वर्चस्व के बीच समय के थपेड़ों के चलते वीर पुरिया को विस्मृत कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में कई इतिहासकारों ने उनके बारे में लिखा, लेकिन उनके योगदान से परिचित होने में नई पीढ़ी वंचित रही। कालांतर कुछ जागरूक लोगों ने उन पर कई किताबें लिखी और उनका स्मारक उनके गांव में बनाने का प्रण लिया। ग्राण नैथाणा में वीर पुरिया स्मारक की आधारशिला 27 अक्तूबर 2021 को रखी गई। लंदन में रहने वाले समाजसेवी डॉ सतीश चंद्र नैथानी ने चार लाख का चेक देकर अभियान की शुरुआत की गई। उनका स्मारक अब बनकर तैयार हो चुका है। उत्तराखंड सरकार की आंशिक मदद के साथ इसके निर्माण में करीब 24 लाख

रुपये का खर्च आया। 31 मार्च 2024 को उनके स्मारक का लोकापर्ण होना है। जिसमें अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ आसपास के 82 गांवों को इसके लिये निमंत्रण दिया गया है। श्री पुरिया ट्रस्ट के संरक्षण निर्मल प्रकाश बताते हैं कि मूर्ति के अनावरण समारोह का खर्च करीब साढ़े चार लाख रुपये अनुमानित है। इस आयोजन में आंशिक मदद उत्तराखंड सरकार ने भी की। जिसमें पुरातत्व विभाग द्वारा उलब्ध कराई गई पांच लाख की मूर्ति भी है। साथ ही तीन लाख रुपये की राशि स्मारक के पिलर निर्माण में भी दी गई। यह स्मारक पहाड़ी ढलाव जमीन पर स्थित होने के कारण दो मंजिले भवन के रुप में बनाया गया।

वीर पुरिया: उत्तराखंड का एक विस्मृत योद्धा पुस्तक के लेखक निर्मल प्रकाश बताते हैं कि वीर पुरिया लंबे अंतराल तक वे एक विस्मृत योद्धा की तरह रहे। इतिहासकारों ने उनके योगदान को नजरअंदाज किया। वे नैथाणा गांव के गौरवशाली पूर्वज थे। ऐसे में उनकी स्मृतियों को संजोने और नई पीढ़ियों को उनके योगदान से अवगत कराने के लिये हमने स्मारक बनाने का संकल्प लिया। कालांतर निर्णय लिया गया कि स्मारक के साथ ही एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया जाए। ताकि देश-विदेश से आने वाले प्रवासियों को गांव में रहने में दिक्कत न हो।

दरअसल, इस काम को आगे बढ़ाने में श्री पुरिया नैथाणी सेवा ट्रस्ट की स्थापना की गई। ट्रस्ट की स्थापना श्रीमती गोदबंरी की प्रयासों से देहरादून में हुई, जिसे श्रीमती विजय सामल के प्रयासों से आगे गति मिली।। कालांतर ट्रस्ट के प्रयासों से सामुदायिक भवन की आधारशिला 27 अक्तूबर 2021 को की गई। सामुदायिक भवन एक डबल स्टोरी के रुप में बनाया जा रहा है। जिसमें सांस्कृतिक आयोजनों के लिये एक हाल भी बनाया जा रहा है। निश्चित रुप से स्मारक के लिये चंदा जुटाना एक बेहद मुश्किल कार्य था। सेवा ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष व वर्तमान संरक्षक निर्मल प्रकाश व वर्तमान प्रधान श्री सुनील गांव-गांव व शहरों में बसे प्रवासी नैथाणावासियों के पास गए। निर्मल नैथानी व उनकी टीम ने गढ़वाल के करीब 32 गांवों में लोगों को संपर्क किया। ये वे गांव थे जहां नैथाणा से प्रवास करके लोग बसे थे। ये ग्रामीण संपन्न वर्ग से नहीं थे, लेकिन इस संपर्क अभियान का उद्देश्य वीर पुरिया की विरासत व स्मारक से सबको जोड़ना भी था। इन सभी गांव में प्रचार-प्रसार के साथ प्रतीकात्मक चंद कार्यक्रम में भागेदारी के लिया गया। साथ ही उन स्थानों को भी छूने का प्रयास किय गया, जहां वीर पुरिया जी के पांव पड़े थे। मकसद उस मिट्टी का प्रणाम करना था जहां हमारे पुरखों के पांव पड़े थे।

दरअसल, निर्मल व उनकी टीम मदन मोहन मालवीय की तरह चंदा जुटाने घर-घर गए। पहले वे अध्यक्ष के रुप में वन मैन आर्मी की तरह जूझे। कालांतर सुनील नैथानी की अध्यक्षता में अभियान चला तो वे निर्मल प्रकाश संरक्षक की भूमिका में आ गये। दरअसल, मिल्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस से सेवानिवृत्त अभियंता के उनके अनुभव स्मारक व सामुदायिक केंद्र के निर्माण में काम आये। उन्होंने वीर पुरिया के योगदान व इस अभियान से जुड़ी पुस्तक –'वीर पुरिया: उत्तराखंड का एक विस्मृत योद्धा' भी लिखा। जिसका विमोचन 22 अगस्त 2020 को पुरिया जी की जयंती पर देहरादून में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था।

श्री पुरिया नैथाणी सेवा ट्रस्ट की एक कामयाबी यह भी रही कि वीर पुरिया के योगदान को उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की पुस्तकों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसके लिये ट्रस्ट को लंबा संघर्ष करना पड़ा। दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने राज्य की पाठ्य पुस्तकों में राज्य के महत्वपूर्ण नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, मेले व सांस्कृतिक पुरुषों को शामिल करने के लिये एक बोर्ड गठित किया। पहले बोर्ड के अधिकारियों ने कहा कि कुछ किताबें लिखने से कोई व्यक्ति इतिहास का हिस्सा नहीं बन जाता। दलील दी कि इन पुस्तकों के लेखक इतिहासकार नहीं थे। ट्रस्ट ने दलील दी कि यू ट्यूब व सोशल मीडिया पर उन पर्याप्त सामग्री मौजूद है। वीर पुरिया पर दिल्ली व अन्य भागों में नाटक खेले गए हैं। तब ट्रस्ट ने उत्तराखंड के प्रतिष्ठित इतिहासकार शिव प्रसाद डबराल, जिनके गढ़वाल के इतिहास पर 22 वैल्यूम मौजूद हैं, हरिकृष्ण रतूड़ी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा व सांस्कृतिक मंत्री रहे भक्तदर्शन द्वारा 26 पेजों में वीर पुरिया के बारे में लिखे लेख व गोविंद चातक द्वारा लिखे इतिहास के दस्तावेज बोर्ड को पेश किये। तब जाकर वीर पुरिया को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। इसमें सेनापति वीर पुरिया द्वारा टिहरी राज्य के अल्पवयस्क वारिस व रानी की कठैत विद्रोहियों से रक्षा से जुड़ अद्वाणी के रानीगढ़ आदि महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख है। साथ ही वीर पुरिया से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों व स्थानों का विवरण शामिल है। ट्रस्ट की कोशिश है कि वीर पुरिया से जुड़े द्वारहाट स्थित नैथाणी गढ़, नैथाणी देवी मंदिर व नैथाणी पहाड़ आदि विवरणों से अगली पीढ़ी को अवगत कराया जा सके। (लेखक अमर शहीद जगदीश वत्स के भांजे व वरिष्ठ पत्रकार है) ●●●

प्रजातंत्र के महापर्व लोक सभा चुनाव 2024 का शंखनाद

प्रजातंत्र के महापर्व लोक सभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। परिणाम स्वरूप इन दिनों वैश्विक राजनीतिक के बदलते परिवेश में भारत की चर्चा चहुँ दिशाओं में हो रही है।चर्चा के केन्द्र में है विश्व के सबसे बड़े व विश्वनीय लोकतंत्र भारत के महापर्व लोक सभा का साधारण चुनाव व 4 राज्यों के विधान सभा चुनावों की। जैसा कि सर्व विदित है यह वर्ष चुनावी वर्ष है।कई देशों भी चुनाव होने वाली है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में चुनाव सम्पन्न हो गए है। वही निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के तारीखों की घोषणा कर दी। यह मतदान 19 अप्रैल से एक जून के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना चार जून को होगी। इस संदर्भ में नई दिल्ली में भव्य विज्ञान भवन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। इसके साथ ही सरकार ऐसा कोई नीतिगत फैसला नहीं कर सकेगी, जो मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सके।

विनोद कुमार सिंह

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार लोकसभा चुनाव 2024 में कुल 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें से 49.7 करोड़ पुरुष, 47.1 करोड़ महिलाएं और 48 हजार ट्रांसजेंडर शामिल हैं। साल 2019 के चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 90 करोड़ थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1.8 करोड़ है, जो पहली बार मतदान करेंगे और मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और सौ साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल हैं।

उन्होने बताया कि देशभर में मतदाता लिंगानुपात 948 है और 12 राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक है।उन्होंने कहा कि देश में 10.5 लाख से अधिक मतदान केंद्र होंगे और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)का इस्तेमाल होगा।

'प्रेस सम्मेलन के अन्तिम चरण में सबाल-जबाव की बारी आई। जिसमें प्रजातंत्र के प्राण व सच्चे प्रहरी कहें जाने वाले पत्रकार की दीर्घा से कई पत्रकारों नें अपनी तरकश से सवालों के कई वाण चलायें। ऐसे ही सात सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बड़ी ही सहजता व साफगोई से तो कुछ के शायर ना अंदाज मेंजवाब दियें।पत्रकारों के प्रशन - मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के द्वारा दिये गए प्रशनों के उत्तर बिन्दुवार निम्न प्रकार है।

1. एक पत्रकार ने पूछा कि विपक्षी दलों का आरोप है कि कई चरणों में चुनाव करवाना ग़ैर-ज़रूरी है और इसका फ़ायदा

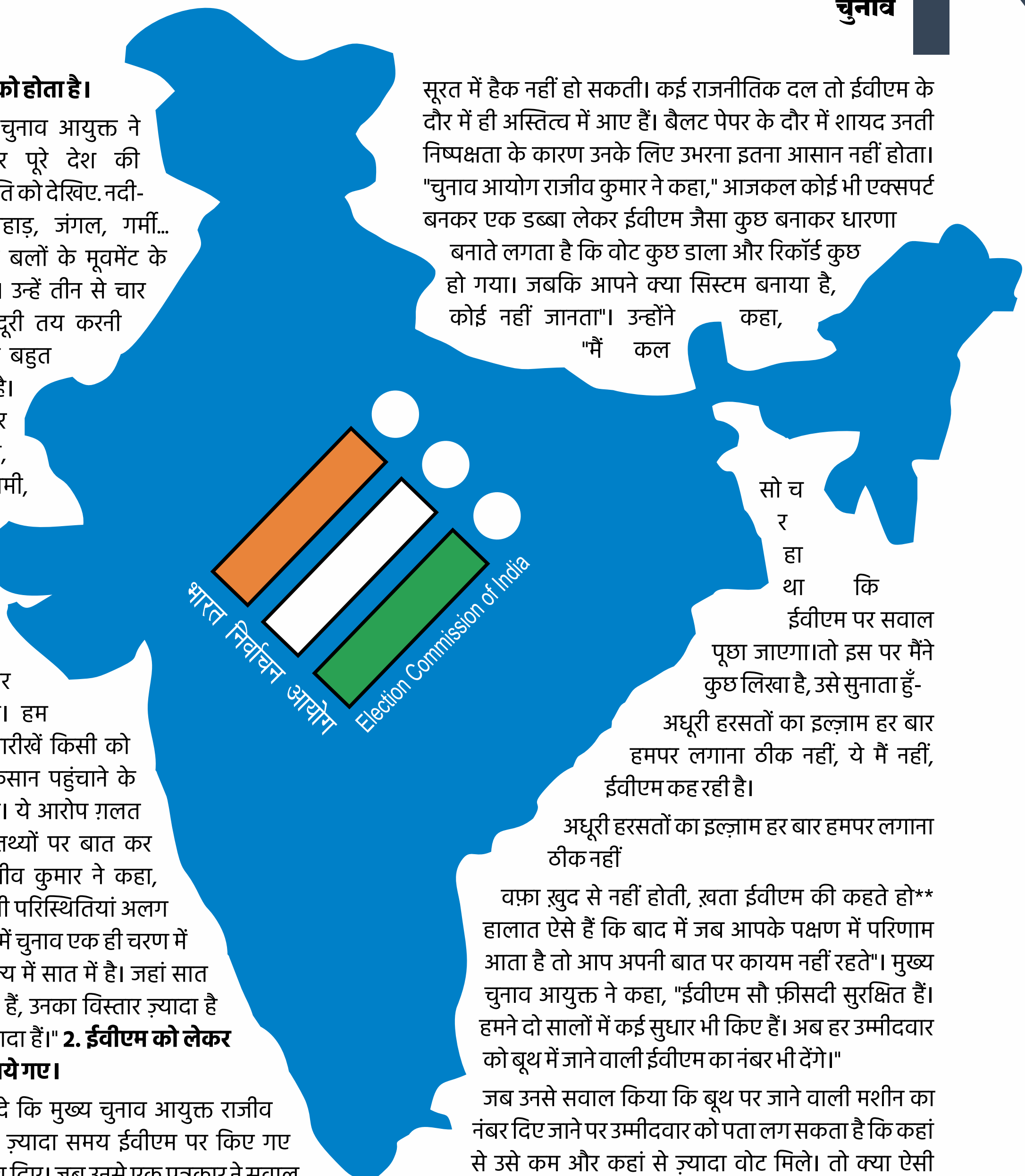

सत्ताधारी दल को होता है।

इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"एक बार पूरे देश की भौगोलिक स्थिति को देखिए. नदी-नाले, बर्फ़, पहाड़, जंगल, गर्मी... सोचिए। सुरक्षा बलों के मूवमेंट के बारे में सोचिए। उन्हें तीन से चार दिन में लंबी दूरी तय करनी होती है। उनपर बहुत दबाव होता है। "देश में त्योहार होते हैं। होली, रमज़ान,राम नवमी, जब हम कैलेंडर देखते हैं तो एक तारीख से दूसरी तारीख पर जाना पड़ता है। हम अलग-अलग तारीखें किसी को फ़ायदा या नुक़सान पहुंचाने के लिए नहीं करते। ये आरोप ग़लत हैं। हम सिर्फ़ तथ्यों पर बात कर सकते हैं। "राजीव कुमार ने कहा, "कई राज्यों में भी परिस्थितियां अलग हैं। किसी राज्य में चुनाव एक ही चरण में है तो किसी राज्य में सात में है। जहां सात चरणों में चुनाव हैं, उनका विस्तार ज़्यादा है और सीटें भी ज़्यादा हैं।" **2. ईवीएम को लेकर कई सवाल उठाये गए।**

आप को बता दे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सबसे ज़्यादा समय ईवीएम पर किए गए सवाल के जवाब दिए। जब उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया था कि विपक्षी दल ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर चिंतित हैं। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा, "ईवीएम को लेकर कई बार सवाल आ चुके हैं। देश की संवैधानिक अदालतों-हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर चुकी है।किसी में कहा गया कि ये हैक हो सकती है, कंप्यूटर से छेड़छाड़ हो सकती है, नतीजे बदल सकते हैं या 19 लाख लापता हैं। मगर हर बार अदालतों ने इन आपत्तियों को खारिज किया।"

उन्होंने ईवीएम पर एक क़िताब दिखाते हुए कहा,"इस क़िताब में हमने सवालों के जवाब भी दिए हैं और 40 मामलों में संवैधानिक अदालतों के फ़ैसलों के बारे में बताया गया है। इसे एक्सपर्ट को भी पढ़ना चाहिए. बताया गया है कि कितनी बार ईवीएम से चुनाव होने के बावजूद सत्ताधारी दलों को सत्ता से हटना पड़ा"

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "अब तो अदालतों ने ईवीएम पर की जाने वाली याचिकाओं को समय की बर्बादी बताते हुए जुर्माना लगाना भी शुरु कर दिया है। ईवीएम किसी भी सूरत में हैक नहीं हो सकती। कई राजनीतिक दल तो ईवीएम के दौर में ही अस्तित्व में आए हैं। बैलट पेपर के दौर में शायद उनती निष्पक्षता के कारण उनके लिए उभरना इतना आसान नहीं होता। "चुनाव आयोग राजीव कुमार ने कहा," आजकल कोई भी एक्सपर्ट बनकर एक डब्बा लेकर ईवीएम जैसा कुछ बनाकर धारणा बनाते लगता है कि वोट कुछ डाला और रिकॉर्ड कुछ हो गया। जबकि आपने क्या सिस्टम बनाया है, कोई नहीं जानता"। उन्होंने कहा, "मैं कल सो च र हा था कि ईवीएम पर सवाल पूछा जाएगा।तो इस पर मैंने कुछ लिखा है, उसे सुनाता हुँ-

अधूरी हरसतों का इल्ज़ाम हर बार हमपर लगाना ठीक नहीं, ये मैं नहीं, ईवीएम कह रही है।

अधूरी हरसतों का इल्ज़ाम हर बार हमपर लगाना ठीक नहीं

वफ़ा ख़ुद से नहीं होती, ख़ता ईवीएम की कहते हो** हालात ऐसे हैं कि बाद में जब आपके पक्षण में परिणाम आता है तो आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते"। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, "ईवीएम सौ फ़ीसदी सुरक्षित हैं। हमने दो सालों में कई सुधार भी किए हैं। अब हर उम्मीदवार को बूथ में जाने वाली ईवीएम का नंबर भी देंगे।"

जब उनसे सवाल किया कि बूथ पर जाने वाली मशीन का नंबर दिए जाने पर उम्मीदवार को पता लग सकता है कि कहां से उसे कम और कहां से ज़्यादा वोट मिले। तो क्या ऐसी स्थिति से बचने के लिए बाद में सभी मशीनों का नतीजा एक साथ देने वाले टोटलाइज़र उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए?

इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा,"मैं मानता हूं कि बूथ के आधार पर नतीजे पता चलाना अच्छा नहीं होता, लेकिन टोटलाइज़र को इस्तेमाल करके कई मशीनों का नतीजा एक साथ देना इसलिए मुश्किल है क्योंकि लोग तो अभी एक मशीन पर ही सवाल उठा रहे हैं। एक साथ कई मशीनों का नतीजा देंगे तो पता नहीं क्या कहेंगे। "उन्होंने कहा कि "राजनीतिक सिस्टम को परिपक्व होने देना चाहिए। नई तकनीकों को लागू करने के लिए समय लगता है। उम्मीद है ऐसा समय आएगा।" आप को बता दे कि बीते दिनों चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। जब एक पत्रकार ने इस संबंध में सवाल किया कि गोयल ने पद क्यों छोड़ा, इस प्रशन के जवाब में उन्होनें कहा कि "वो हमारी टीम के ख़ास सदस्य थे, उनके साथ काम करना अच्छा लगा, लेकिन हर संस्थान में लोगों को पर्सनल स्पेस देना चाहिए। अगर उन्होंने निजी कारण बताए हैं तो उस मामले में निजी सवाल नहीं किए जा सकते।"

"वैसे भी हमारे पूर्ववर्ती लोगों ने चुनाव आयोग को ऐसी जगह बनाया है, जहाँ असहमतियों का भी सम्मान किया जाता है। तो यहां चर्चा होती है, असहमतियां भी होती हैं और ये होती रहनी चाहिए" **5. आचार संहिता उल्लंघन पर 'दोहरे मापदंड' क्यों?**

राजीव कुमार ने अपने भाषण में चुनाव आयोग की जिन चार मुख्य चुनौतियों का ज़िक्र किया, उनमें चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन भी शामिल है। पत्रकार ने सवाल किया कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कई शिकायतों पर यह देखने को मिला कि चुनाव आयोग ने उस तरह से एक्शन नहीं लिया, जैसी कार्यवाही विपक्षी नेताओं को लेकर लिया जाता है। इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ये एक तरह से हमारे ऊपर आरोप है. सवाल पूछने का अधिकार है आपको पिछले 11 चुनावों में हमारे पास जितने भी आरोप आए, उनपर हमारे नोटिस देखिए "जब भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप स्थापित होता हो, उसका जवाब आने के बाद ऐसा नहीं है कि हमने कार्रवाई नहीं की है। जिस किसी पर भी कोई मामला बनेगा, वह कितना भी बड़ा स्टार कैंपेनर क्यों न हो, हम बैठेगें नहीं, क़दम उठाएंगे."

आदर्श आचार संहिता क्यों लाई गई और ये क्या काम करती है?

16 मार्च 2024 टीएन शेषन: जो 'खाते थे राजनीतिज्ञों को नाश्ते में!' 1 अप्रैल 2019 (6)जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव क्यों नहीं?कश्मीर मुख्य चुनाव आयुक्त ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न करवाने की दो वजहें बताईं.

उन्होंने कहा,"जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में बना था. इसमें 107 विधानसभा सीटों का प्रावधान था जिनमें से 47 सीटें पीओके के लिए थीं. लेकिन फिर 2022 में पुनर्सीमांकन किया गया तो राज्य की सीटें 107 से 114 हो गईं. फिर इसमें आरक्षण का भी प्रावधान था।फिर दिसंबर में इस आधार पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन किया गया,लेकिन तब तक हम लोकसभा चुनावों की तैयारी में लग गए थे।"जब हम कश्मीर में लोगों से मिलने गए तो वहां राजनीतिक दलों का कहना था कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवा दीजिए. लेकिन वहां प्रशासन का कहना था कि ऐसा करना संभव नहीं होगा,क्योंकि 1000 के क़रीब उम्मीदवार होंगे और हर उम्मीदवार को कम से कम दो सेक्शन फ़ोर्स सुरक्षा के लिए देनी पड़ती है। 7.कैश की बरामदगी पर क्या कार्रवाई होती है।मुख्य चुनाव आयुक्त ने आयोग की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा था कि हाल ही में हुए11राज्यों के विधानसभा चुनावों में क़रीब 3500 करोड़ रुपये की नकदी पकड़ी गई थी।इस पर एक पत्रकार ने कहा कि इस कैश की बरामदगी में कितने लोग जेल गए,कौन सी पार्टियों के लोग शामिल थे,इसकी जानकारी साझा नहीं की जाती।

इस सबाल पर सीधे कोई जवाब नहीं दिया,लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु के वेल्लोर में एक प्रत्याशी के पास करोड़ों रुपये मिलने पर क्या कार्रवाई हुई थी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, "कई राज्यों में धनबल का ज़ोर ज़्यादा देखने को मिलता है. हम इस पर गंभीर हैं. अगर आप अन्य दक्षिण राज्यों में हाल के समय में हुए चुनावों पर नज़र डालेंगे तो पाएंगे कि इस समस्या पर हमने काफ़ी हद तक लगाम लगाई है. आप चिंता न करें."

खैर - भारत जैसे विश्व के सबसे बडे व चर्चित लोकतंत्र में आम चुनाव कराने कोई आसान बात नही है।वह जब यहाँ भौगोलिक ' सांस्कृतिक ' राजनीतिज्ञ ' की विविघिताओ से भरे देश में निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए आसान नही है।

भारतीय राजनीतिज्ञ दलो ने अपनी उम्मीदवारों को चुनाव में जताने के अपनी -अपनी कमर कस ली है।लोकचुनाव सभा की तारीख की ऐलान के बाद अचार संहिता भी लागू हो गई ।

ऐसे प्रजातंत्र के सफलता में भारतीय जनता की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वे अपने मतों का उपयोग अवश्य कर चुनाव रुपी महायज्ञ में अपनी आहुति अवश्य डाल कर सच्चे भारतीय होने का गर्व प्राप्त करें।

अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति-जीजाबाई

डा0 आकांक्षा दीक्षित

युद्धक्षेत्र के शिविर में किसी की प्रतीक्षा में रत तेजस्वी युवक इधर से उधर चहलकदमी कर रहा था। अचानक अपने सेनानायक को आते देख प्रसन्न होकर उसकी ओर बढ़ता है कि उसकी दृष्टि उसके पीछे लाई जा रही पालकी पर पड़ती है। उनकी दृष्टि में प्रश्न और आश्चर्य दोनों सम्मिलित थे। सेनानायक आकर अभिवादन करता है और विजय का समाचार सुनाकर युद्ध में जीती गई सम्पत्ति समर्पित करता है।

अचानक धीर-गंभीर स्वर में उससे पूछा जाता है कि' ये तो ठीक है ,बड़ी प्रसन्नता की बात है किंतु इस पालकी में क्या है ?'

सेनापति उत्साहित होकर बताता है कि -'राजे! ये पराजित बहलोल खां की बेगम अतीव सुंदरी गौहर बानू है ,ये आपका विजय उपहार है। ' हतप्रभ से राजे आग्रेय दृष्टि से सेनानायक को देखते हुए पालकी के निकट जाकर उस सिंहों के मध्य फंसी भयभीत हरिणी सदृश नारी को बाहर आने को कहते है। उनके बाहर आते ही वे उन्हें देखते है और सम्मान पूर्वक कहते है कि ,'आप सचमुच अनिंद्य सुंदरी है , आपको देखकर मेरा मन कहता है कि यदि मेरी मां भी इतनी सुंदर होती तो कदाचित मैं भी थोड़ा सौन्दर्य पा जाता।' एक युद्ध में हस्तगत स्त्री को अपने प्रति मातृवत संबोधन सुनकर जो अनुभव हुआ होगा उसको अभिव्यक्त करना संभव नहीं है। सेनानायक जो सर झुकाए खड़ा था ,उससे राजे ने कहा कि ,' भूलों मत ,हम उस संस्कृति को मानने वाले है ,जहां स्त्री देवी का प्रतीक है , प्रत्येक पराई स्त्री भले ही वो शत्रु के परिवार की हो ,हमारी मां, बहन और पुत्री के समान है। आज के बाद ऐसी धृष्टता नहीं होनी चाहिए।'

ये चारित्रिक दृढ़ता और नारी के प्रति अपूर्व सम्मान का भाव रखने वाले शिवाजी राजे के जीवन की सत्य घटना है। गौहर बानू को तत्काल उनके पति के पास पूरे आदर से भिजवाने वाले शिवाजी को ये अद्भुत जीवनमूल्य देने का श्रेय उनकी माता जीजाबाई को है। जीजाबाई ने एक पुत्र का नहीं वरन वीर, साहसी ,धैर्यवान , चरित्रवान , संवेदनशील, नेतृत्वकर्ता , स्वराज्य के लिए आजीवन संघर्षरत योद्धा का पालन-पोषण किया था। उन्होंने उसे दूध के साथ स्वदेशप्रेम और चारित्रिक मूल्य भी पिलाए थे। ये भारत की नारी की ही शक्ति है कि वह विपरीत परिस्थितियों मिल भी टूटकर बिखरती नहीं बल्कि संघर्ष ज्वाला में तपकर कुंदन की तरह बन जाती है और अपनी संतति को भी ऐसी ही शिक्षा देती है। यही नहीं मां की इच्छा और प्रण को पूर्ण करने के लिए कोंढ़ाना का दुर्ग शिवाजी अपने मित्र और सेनानायक तानाजी मालसुरे के अदम्य साहस और बलिदान के बाद विजित किया था। इतिहास में ऐसा उदाहरण भी दुर्लभ ही है कि एक युद्ध माँ के संकल्प को पूरा करने के लिए लड़ा भी गया और जीता भी गया। यही नहीं शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बनाने में जो प्रेरणा और ऊर्जा थी वो माता जीजाबाई की ही थी। जिसप्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण कुंदन बनता है उसीप्रकार परिस्थितियों की आग और स्वदेश , सुराज , हिन्दूपदपादशाही स्थापित करने के दुर्घर्ष संकल्प से जीजाबाई ने

शिवाजी को गढ़ा था । शताब्दियों से जो छत्रपति की कीर्तिपताका लहरा रही है उसका मूल माता जीजाबाई ही थी । माता को हमारी संस्कृति सर्वोच्च स्थान देती है ।

'प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य समा तृमान ।'

भावार्थ यह कि वह माता बहुत महान है जो अपने बच्चे को अपने गर्भधान से लेकर उसकी शिक्षा पूर्ण होने तक उसके उचित आचरण का पूर्ण ध्यान देती है। यह श्लोक जीजाबाई पर खरा उतरता है । ऐसी भारत की महान नारी राजमाता जीजाबाई का जन्म 12 जनवरी 1598 को महाराष्ट्र के वर्तमान बुलढाणा जिले के सिंदखेड राजा में म्हालासाबाई जाधव और लखुजी जाधव के घर हुआ था।जीजाबाई को प्यार से 'जिउ' कहा जाता था। लखुजीराजे जाधव एक मराठा कुलीन थे जिन्होंने यादवों से वंश से होने दावा था उनका वंश देवगिरि के यादव राजवंश से जुड़ा था। इसप्रकार जीजाबाई को राजकुमारी जैसा दर्जा प्राप्त था । हालाँकि जैसे-जैसे उसके परिवार ने सुल्तान की सेना में पद ग्रहण किया, उसका असंतोष बढ़ता गया। उन्होंने आक्रमणकारियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए दुर्व्यवहार और अपमान को देखा। अन्याय के इस शुरुआती प्रदर्शन ने जीजाबाई के मन में उन लोगों के प्रति तीव्र घृणा भर दी जो उनके लोगों को अपने अधीन करना चाहते थे। इसने उनके भविष्य के संघर्षों की नींव रखी। सुल्तान की सेना के एक प्रसिद्ध सेनापति शाहजीराजे भोसले से जीजाबाई का विवाह नई चुनौतियाँ लेकर आया। मराठा सरदारों के बीच संघर्ष के बीच, जीजाबाई और शाहजी ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध स्वराज्य की संकल्पना से एक एकीकृत मोर्चे की कल्पना की। हिंदू साम्राज्य के लिए उनकी महान आकांक्षाओं को अहंकार से प्रेरित

मराठा सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता कभी नहीं डिगी। आक्रमणकारियों से एकता और मुक्ति की शक्ति में जीजाबाई का उत्कट विश्वास सबसे अंधकारमय समय में भी स्थिर रहा। समय अपनी गति से आगे बढ़ा और एक नया संघर्ष सामने आ खड़ा हुआ। इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान जब निज़ाम की सेना द्वारा शाहजीराजे का पीछा किया गया था, उस समय गर्भवती जीजाबाई ने शिवनेरी किले की सुरक्षा में शरण ली थी। अपने पिता के साथ उसका पुनर्मिलन एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। मराठा एकता और आक्रमणकारियों से मुक्ति के लिए जीजाबाई की भावुक अपील ने उनके भीतर एक राग छेड़ दिया, जिससे एक सुलह हुई जिससे जाधव और भोसले के बीच शत्रुता हमेशा के लिए समाप्त हो गई। इस मेल-मिलाप ने जीजाबाई की विभाजन को पाटने और सामूहिक उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने की क्षमता को प्रदर्शित किया।

शिवाजी महाराज जयंती पर माता जीजाबाई से रिश्ता हर किसी को गौरवान्वित करता है|

जीजाबाई की अटूट भक्ति उनकी रानी और माँ की भूमिका से भी आगे तक फैली हुई थी। पुणे में, उन्होंने सक्रिय रूप से समुदाय में योगदान दिया, मंदिरों की स्थापना की और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। उनकी गहरी आध्यात्मिकता मात्र

अनुष्ठानों से परे थी, क्योंकि उन्होंने खुद को भजन-कीर्तन में डुबो दिया, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया और धर्म द्वारा निर्देशित जीवन अपनाया। जीजाबाई का गहरा विश्वास कि सफलता ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है, उनकी ताकत और लचीलेपन का आधार बनी । उन्होंने पुणे में अपने पति की जागीर का प्रबंधन किया और उसका विकास किया। उन्होंने कसबा गणपति मंदिर की स्थापना की। उन्होंने केवरेश्वर मंदिर और तम्बाड़ी जोगेश्वरी मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। एक आदर्श हिंदू महिला के रूप में जीजाबाई की विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। एक बेटी, बहन, पत्नी, मां और दादी के रूप में उनकी उल्लेखनीय यात्रा हिंदू धर्मग्रंथों में बताए गए गुणों का उदाहरण है। अपने परिवार द्वारा प्यार और सम्मान पाने के कारण, उन्होंने शक्ति और करुणा का प्रतीक बनकर समर्थन के स्तंभ के रूप में काम किया। जीजाबाई का जीवन अटूट विश्वास, वीरता और एकता की परिवर्तनकारी क्षमता की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। जीजाबाई का जीवन अदम्य भावना और अटूट भक्ति का एक स्थायी प्रमाण है जो इतिहास को आकार दे सकता है। अपने राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, अटूट विश्वास और धर्म का निरंतर अनुसरण हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। जीजाबाई की कहानी हमें लचीलेपन, एकता की शक्ति और इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में एक व्यक्ति के गहरे प्रभाव की याद दिलाती है। वीरता और भक्ति की प्रतीक के रूप में उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शाश्वत प्रेरणा के रूप में खड़ी है।

जीजाबाई की चारित्रिक दृढ़ता, धर्म परायणता, वीरता , दूरदर्शिता उनके पुत्र शिवाजी में स्थानांतरित भी हुई और द्विगुणित भी।

शाहजी राजे भोसले और जीजाबाई के दूसरे बेटे, शिवाजी का जन्म फरवरी 1630 में हुआ था। उनके बड़े बेटे संभाजी अपने पिता के साथ रहते थे और कम उम्र में एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी। अपने बड़े भाई की याद में शिवाजी राजे ने अपने बड़े बेटे का नाम संभाजी राजे रखा। जब शिवाजी 14 वर्ष के थे, तब शाहजी राजे ने उन्हें पुणे की जागीर सौंप दी । जागीर के प्रबंधन की जिम्मेदारी जीजाबाई पर आ गई। जीजाबाई और शिवाजी राजे कुशल अधिकारियों के साथ पुणे पहुंचे। निज़ामशाह , आदिलशाह और मुग़लों के लगातार स्वार्थ के कारण पुणे की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने पुणे शहर का पुनर्विकास किया। उसने स्थानीय लोगों को आश्रय देते हुए, सुनहरे हल से खेत की जुताई की। वह शिवाजी राजे की शिक्षा के लिए उत्तरदायी थीं। जीजाबाई ने शिवाजी राजे को रामायण , महाभारत की कहानियाँ सुनाईं , जिनके साथ जीवन मूल्य भी उनके चरित्र में समाहित हो सके । शिवाजी को संकट के समय धैर्य धारण करने का सबक भी अपनी माता से ही मिला था जिसके कारण उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखा । इससे ना केवल कपटी अफज़ल खां का वध कर सके वरन औरंगजेब की कैद से भी चतुराई से बाहर निकल सके । इसी मां के संस्कारों के फलस्वरुप उन्होंने अफजल खा का अंतिम संस्कार मुस्लिम पद्दति से करवाया। यही नहीं छत्रपति शिवाजी ने अपनी इसी शिक्षा को सार्थक करते हुए अपनी माता को भी सती होने से रोका। जब जीजाबाई के पति शाहजी राजे की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने सती प्रथा के अनुसार खुद को बलिदान करने का निर्णय किया था किन्तु शिवाजी महाराज ने इसका विरोध किया और उन्हें सती होने से रोका।ऐसी विलक्षण माता ही ऐसा प्रतिभावान, साहसी, चारित्रिक रुप से आदर्श, स्वराज्य के लिए संकल्पित पुत्र को देश के लिए समर्पित कर सकती है। भारत की महान नारियों में जीजाबाई सदैव स्तुत्य, आदरणीय, वंदनीय और अनुकरणीय रहेंगी। ●●●

स्वास्थ्य के प्रति जन जागरण को समर्पित है विश्व स्वास्थ्य दिवस का वैश्विक आयोजन

डा. महेंद्र राणा

विश्व के सबसे प्राचीन चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद में स्वास्थ्य को व्यक्ति की सबसे बहुमूल्य पूंजी बताते हुए कहा गया है कि "लाभानाम श्रेष्ठ आरोग्यम"। एक स्वस्थ्य शरीर में ही स्वस्थ्य मस्तिष्क का निर्माण हो सकता है और स्वस्थ मस्तिष्क से ही समृद्ध मानवता का विकास हो सकता है। व्यक्ति पूर्ण रुप से तभी स्वस्थ माना जाएगा जब वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रुप से सहज महसूस करता हो। समग्र स्वास्थ्य शारिरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक सहजता की संतुलित अवस्था है और इसी जागरुकता को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व स्वास्थ्य दिवस का आयोजन होता है। यह दिवस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य विषयों को उजागर करने और लोगों को अपने अच्छे स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

हाल ही में एक रिपोर्ट में WHO ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) स्वास्थ्य और उसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति पर जोर देता है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति पर। उनका मानना है कि सभी को स्वास्थ्य का उच्चतम संभव स्तर प्राप्त होना चाहिए और स्वास्थ्य सभी का मौलिक अधिकार है। वे साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि, 1. वैश्विक वैक्सीन कार्य योजना, 2. वैश्विक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रतिक्रिया, 3. मानसिक स्वास्थ्य कार्य योजना, 4. तंबाकू नियंत्रण, 5. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और कई अन्य के माध्यम से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं।

वैसे, वैश्विक स्तर पर, स्वास्थ्य की स्थिति एक जटिल और गतिशील विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार विभिन्न देशों और क्षेत्रों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी और मूल्यांकन करता है। वे विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों, जैसे जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, बीमारी की व्यापकता और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच कर रिपोर्ट प्रदान करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक प्रथाओं या किसी भी प्राकृतिक प्रकोप जैसे कारकों के कारण विभिन्न देशों और आबादी में स्वास्थ्य की स्थिति अलग-अलग हो सकती है। वर्तमान में युद्ध और कुछ प्राकृतिक प्रकोपों के कारण स्वास्थ्य की स्थिति बहुत जटिल है, जिसके कारण मृत्यु दर और स्वास्थ्य बार एक निश्चित बिंदु पर बढ़ गए हैं।

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी दी है। भारत में कुछ प्रमुख स्वास्थ्य मुद्दों में तपेदिक और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियों का उच्च बोझ, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में चुनौतियाँ और मधुमेह और हृदय संबंधी बीमारियों जैसी गैर-संचारी बीमारियों का बढ़ता प्रचलन और कोरोना जैसी कुछ प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत ने टीकाकरण कवरेज और बाल मृत्यु दर को कम करने जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत की जनसंख्या स्वास्थ्य गतिशीलता बहुआयामी है, जिसमें कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कारक इसके लोगों के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। भारत के स्वास्थ्य परिदृश्य की विशेषता दो-तरफा बीमारी का बोझ है, जिसमें संचारी रोगों

का दीर्घकालिक प्रचलन और हृदय रोग, मधुमेह और श्वसन रोगों जैसे एनसीडी (गैर-संचारी रोग) का तेज़ी से बढ़ता प्रचलन है। तपेदिक, मलेरिया और एचआईवी/एड्स जैसी संक्रामक बीमारियाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खतरा बनी हुई हैं, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतक चिंताजनक बने हुए हैं, जिनमें मातृ एवं नवजात मृत्यु दर तथा बाल कुपोषण की उच्च दरें शामिल हैं। तपेदिक, मलेरिया और अन्य संक्रामक रोग विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2021 के अनुसार, भारत में औसत जीवन प्रत्याशा 70.8 वर्ष है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के अनुसार, भारत में शिशु मृत्यु दर (I M R) 2019 से 2021 तक प्रति 1,000 जन्मों पर 35 थी, जो 2015-16 की संख्या से 15 प्रतिशत कम है। इसके अलावा, भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए वैश्विक कार्य योजना 2013-2020 को अपनाने वाले पहले देशों में से एक रहा है, जिसका लक्ष्य 2025 तक 25 प्रतिशत एनसीडी में कमी लाना है।

खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने के लिए कुछ सुझाव स्वस्थ रहने के लिए आपको इन सुझावों का पालन करना चाहिए:

- संतुलित आहार लें: अपने भोजन में फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें।
- शारीरिक रूप से सक्रिय रहें: प्रति सप्ताह कम से कम 150 मिनट तक नियमित व्यायाम या शारीरिक गतिविधि में शामिल हों।
- तम्बाकू से बचें और शराब का सेवन सीमित करें: धूम्रपान छोड़ें और सेकेंड हैंड धूम्रपान से बचें। अगर आप शराब पीते हैं, तो संयम से पिएँ 4. सुरक्षित सेक्स करें: यौन संचारित संक्रमणों से बचने के लिए कंडोम का उपयोग करें और नियमित जाँच करवाएँ।
- टीका लगवाएँ: संक्रामक रोगों से बचने के लिए टीकाकरण करवाते रहें।
- अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें: अपने हाथों को बार-बार धोएँ, खाँसते या छींकते समय अपना मुँह ढँकें और स्वच्छता बनाए रखें।
- मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें: तनाव प्रबंधन, सामा जिक संपर्क और ज़रूरत पड़ने पर मदद माँगने के ज़रिए अपने भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
- नियमित स्वास्थ्य जाँच कर वाएँ: नियमित जाँच और जाँच के लिए स्वा स्थ्य सेवा पेशे वरों से मिलें।

(लेखक वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक, आरोग्य मेडीसिटी इंडिया के संस्थापक एवम् भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखंड सरकार के पूव र्सदस्य हैं) ●●●

महादेव ने भूत-प्रेत के साथ खेली चिता भस्म की होली

काशी में खेली गई विश्व प्रसिद्ध मसाने की होली पूरे विश्व में सिर्फ काशी में ही खेली जाती है
चिता-भस्म की होली पर्यटकों ने देखा दिगंबर के मसाने की होली का अद्भुत नज़ारा
भारी उत्साह के साथ जलती चिताओं के बीच "चिता भस्म "की होली
विदेशी पर्यटकों ने भी इस उत्सव का जमकर लुफ्त उठाया

अनिल द्विवेदी

काशी के मणिकर्णिका घाट पर गुरुवार को अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहां बड़े ही उत्साह के साथ जलती चिताओं के बीच "चिता भस्म " की होली खेली गई। मसाने की होली खेलने के लिए मणिकर्णिका घाट के महाश्मशान पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ मणिकर्णिका के महाश्मशान में अपने गणों के साथ चिता भस्म की होली खेलते हैं।

सिर्फ काशी में खेली जाती है ऐसी होली

पूरे देश में रंगों और गुलालों से होली खेली जाती है, लेकिन शिव की नगरी काशी में चिता की राख के साथ भी होली खेली जाती है। ऐसी होली पूरे विश्व में सिर्फ काशी में मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर भस्म की होली अपने प्रिय गण भूत, प्रेत, पिशाच शक्तियों के साथ खेलते हैं।

विदेशी पर्यटकों ने भी उठाया लुत्फ

चिता भस्म की होली शुरु करने से पहले बाबा मसान नाथ की पूरे विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है। फिर बाबा की आरती करने के बाद चिता के राख से होली की शुरुआत की जाती है, जिसमें ढोल-नगाड़े और डमरु के साथ पूरा श्मशान घाट हर-हर

महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। काशीवासियों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी इस उत्सव का जमकर लुफ्त उठाया।

क्यों मनायी जाती है मसान की होली

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने मसान की होली की शुरुआत की थी। ऐसा माना जाता है कि रंगभरी एकादशी के दिन भगवान शंकर माता पार्वती का गौना कराने के बाद उन्हें काशी लेकर आए थे। तब उन्होंने अपने गणों के साथ रंग-गुलाल के साथ होली खेली थी, लेकिन वे श्मशान में बसने वाले भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष गन्धर्व, किन्नर जीव जंतु आदि के साथ होली नहीं खेल पाए थे, इसलिए रंगभरी एकादशी के एक दिन बाद भोलेनाथ ने श्मशान में रहने वाले भूत-प्रेत साथ होली खेली थी। तभी से काशी में मसान की होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। चिता की राख से होली खेलने की वजह से ये परंपरा देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। ●●●

पराली अब समस्या नहीं, आमदनी का जरिया

आने वाले समय में प्रदेश में होंगे सौ सीबीजी प्लांट
पराली प्रबंधन के लिए किसानों में सरकार 17 लाख बायो डीकंपोजर भी बांटेगी

ब्यूरो कार्यालय

आम के आम और गुठलियों के दाम की कहावत अब यूपी के किसानों के जीवन में चरितार्थ होगी। फसल काटने के बाद उनके और पर्यावरण के लिए समस्या मानी जाती रही पराली भी अब आमदनी और ऊर्जा का जरिया बन रही है। यह संभव हो रहा है सीबीजी (कम्प्रेस्ड बायो गैस) प्लांट से। सीबीजी प्लांट में पराली से ईंधन तैयार हो रहा है और ईंधन बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किसानों से उनकी पराली खरीदी जा रही है। हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में दस सीबीजी प्लांट क्रियाशील हो चुके हैं। आने वाले समय में प्रदेश में इनकी संख्या बढ़कर सौ हो जाएगी। इसी महीने की आठ तारीख को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसकी घोषणा भी कर चुके हैं।

यंत्रीकरण के बढ़ते चलन और श्रमिकों की अनुपलब्धता होने की वजह से अब फसलों की कटाई कंबाइन से ही होती है। खरीफ और रबी की प्रमुख फसल धान और गेहूं की कटाई के बाद अगली फसल की तैयारी के लिए इन फसलों के अवशेष जलाने की प्रथा आम है। इसके कारण खासकर धान की कटाई के बाद मौसम में नमी के कारण यह समस्या कुछ इलाकों में गंभीर हो जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस समस्या

अन्य लाभ

फसल अवशेष से ढकी मिट्टी का तापमान नम होने से इसमें सूक्ष्मजीवों की सक्रियता बढ़ जाती है, जो अगली फसल के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व मुहैया कराते हैं।

अवशेष से ढकी मिट्टी की नमी संरक्षित रहने से भूमि के जल धारण की क्षमता भी बढ़ती है। इससे सिंचाई में कम पानी लगने से इसकी लागत घटती है। साथ ही दुर्लभ जल भी बचता है।

का स्थाई हल निकालने के लिए शिद्दत से लगी है। इससे संबंधित योजनाएं जब तक अमल में आएं तब तक के लिए भी सरकार की यह मंशा है कि हर संभव तरीकों से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या को कम किया जाय। इस दिशा में सीबीजी प्लांट एक शानदार विकल्प बनकर सामने आया है।

सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 का जो ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें कृषि अपशिष्ट आधारित बायो सीएनजी, सीबीजी इकाइयों को कई तरह के प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। सरकार की मंशा हर जिले में सीबीजी प्लांट लगाने की है। इसी कड़ी में 8 मार्च को गोरखपुर के धुरियापार में इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का शुभारंभ हो चुका है। इसके उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उपस्थित रहे केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आने वाले समय में यूपी में सीबीजी प्लांट की वर्तमान संख्या दस को सौ के आंकड़े तक ले जाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

वास्तव में 165 करोड़ रुपये के निवेश वाला गोरखपुर का यह सीबीजी प्लांट पर्यावरण की रक्षा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा प्रयास है। इस प्लांट में रोजाना 200 मीट्रिक टन पराली यानी कृषि अवशेष (धान का भूसा) 20 मीट्रिक टन प्रेसमड और 10 मीट्रिक टन मवेशियो के गोबर का उपयोग होगा। बायोगैस प्लांट में प्रतिदिन लगभग 20 मीट्रिक टन बायोगैस और 125 मीट्रिक टन जैविक खाद का उत्पादन होगा। जैविक खाद से कृषि की पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी इस तरह के प्लांट का सीधा मतलब यह हुआ कि ऊर्जा क्षेत्र में भी अन्नदाता किसानों की बड़ी भूमिका होगी। और, इस ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र से जुड़कर वह अतिरिक्त आय भी अर्जित करेंगे। उधर

विकल्प

डंठल जलाने के बजाय उसे गहरी जोताई कर खेत में पलट कर सिंचाई कर दें। शीघ्र सड़न के लिए सिंचाई के पहले प्रति एकड़ 5 किग्रा यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए कल्चर भी उपलब्ध हैं

पराली जब जलाई नहीं जाएगी तो पर्यावरण संरक्षण आप ही होने लगेगा। सीबीजी प्लांट को प्रोत्साहित करने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि वह धान की पराली को बायोकपोस्ट में बदलने के लिए 17 लाख किसानों को बायो डीकंपोजर उपलब्ध कराएगी। इस बीच जागरुकता और अन्य अभियान भी जारी रहेंगे।

पराली जलाने के क्या हैं दुष्प्रभाव

अगर आप कटाई के बाद धान की पराली जलाने की सोच रहे हैं तो रुकिए और सोचिए। आप सिर्फ खेत नहीं उसके साथ अपनी किस्मत खाक करने जा रहे हैं। क्योंकि पराली के साथ फसल के लिए सर्वाधिक जरूरी पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश (एनपीके) के साथ अरबों की संख्या में भूमि के मित्र बैक्टीरिया और फफूंद भी जल जाते हैं। भूसे के रूप में पशुओं का हक तो मारा ही जाता है।

पराली में है पोषक तत्वों का खजाना

शोधों से साबित हुआ है कि बचे डंठलों में एनपीके की मात्रा क्रमशः 0.5, 0.6 और 1.5 फीसद होती है। जलाने की बजाए अगर खेत में ही इनकी कंपोस्टिंग कर दी जाय तो मिट्टी को यह खाद उपलब्ध हो जाएगी। इससे अगली फसल में करीब 25 फीसद उर्वरकों की बचत से खेती की लागत में इतनी ही कमी आएगी और लाभ इतना ही बढ़ जाएगा। भूमि के कार्बनिक तत्वों, बैक्टिरिया फफूंद का बचना, पर्यावरण संरक्षण और ग्लोबल वार्मिंग में कमी बोनस होगा। गोरखपुर एनवायरमेंटल एक्शन ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार प्रति एकड़ डंठल जलाने पर पोषक तत्वों के अलावा 400 किग्रा उपयोगी कार्बन, प्रतिग्राम मिट्टी में मौजूद 10-40 करोड़ बैक्टीरिया और 1-2 लाख फफूंद जल जाते हैं।

उप्र पशुधन विकास परिषद के पूर्व जोनल प्रबंधक डा. बीके सिंह के मुताबिक प्रति एकड़ डंठल से करीब 18 क्विंटल भूसा बनता है। सीजन में भूसे का प्रति क्विंटल दाम करीब 400 रुपए माना जाए तो डंठल के रूप में 7200 रुपये का भूसा नष्ट हो जाता है। बाद में यही चारा संकट का कारण बनता है। ●●●

समय पूर्व सेवानिवृत्ति को ऐसे बनाएं वित्तीय रूप से खुशहाल

रितु प्रसाद

सेवानिवृत्ति की बात चलते ही हम अपने आप सोचने लगते हैं कि 60 साल के या उपर के हो गए हैं। क्या होगा अगर हम अपनी सेवानिवृत्ति को समय से पहले कर लें- 50 साल की आयु पर या उससे भी पहले। ये कठिन या असंभव लगता है लेकिन यह हो सकता है अगर इसे सुनियोजित तरीके से व ढंग से संपादित किया जाए।

समय से पहले सेवानिवृत्ति की योजना पर काम करने से पहले आपको अपनी वित्तीय दशा पर दूरदृष्टि डालते हुए स्पष्टता बरतनी होती और वित्तीय मजबूती के लिए पहले से योजना बनानी होगी। इसमें शामिल होता है अपने वित्तीय लक्ष्यों को पहचानना, वर्तमान वित्तीय स्थिति का आकलन और एक व्यापक योजना तैयार करना जिसमें बचत, निवेश व खर्च कवर होते हैं। इस लेख में हम कुछ आवश्यक कदमों का उल्लेख करेंगे जिन्हें आप समय पूर्व सेवानिवृत्ति की योजना बनाते हुए उठा सकते हैं और अपने लिए वित्तीय रुप से सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं।

प्रथम और सबसे पहले: कार्पस की गणना

सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सेवानिवृत्ति के बाद के कार्पस की गणना करना क्योकि इसी से तय होगा कि आपको सेवानिवृत्ति तक कितने पैसों की बचत और निवेश करना है जिससे कि आपको वित्तीय स्वतंत्रता मिल सके व आगे इच्छित जीवनशैली बरकरार रहे। योजना बनाते समय यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि बचत किया हुआ पैसा व्यय न हो जाए। इसके अतिरिक्त यह साल दर साल बढ़ता रहे और आदर्श स्थिति यह होगी कि मुद्रास्फीति से ज्यादा वृद्धि हो।

उदाहरण के लिए अगर आप 25 साल के हैं और 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति की सोच रहे हैं। आपका मासिक खर्च 2023 में 40000 रुपये का है। तो 6 फीसदी मंहगाई दर को मानते हुए जब अगले 15 वर्षों में आप 40 वर्ष के होंगे तब आपका मासिक खर्च करीब 95862 रुपये होगा। इसके साथ ही मंहगाई का असर आप पर सेवानिवृत्ति के बाद भी पड़ता रहेगा। इसे देखते हुए आपके सेवानिवृत्ति कार्पस पर इस सबका असर दिखना चाहिए।

यदि आपको 40 वर्ष की आयु में 11.5 लाख प्रति वर्ष खर्च के लिए चाहिए तो ये रकम मंहगाई के चलते 70 या 80 वर्ष की आयु आते आते और भी बढ़ जाएगी। इसलिए सेवानिवृत्ति कार्पस की गणना करते समय हर साल बढ़ने वाले खर्च को शामिल करना चाहिए।

फायर मैथेड

समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए पैसे बचाने का एक अन्य तरीका है एफ.आई.आर.ई (फाइनैंशिएल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली) मैथेड। फायर मैथेड में मितव्ययी जीवनशैली पर जिसमें अधिकतम बचत, ऋणों से जल्दी छुटकारा और आक्रामक निवेश पर सक्रिय रिटर्न हासिल करना मुख्य केंद्रबिंदु होता है। फायर मैथेड के मूल सिद्धांतों में शामिल होता है खर्च घटाना, आय बढ़ाना, तेजी से बचाना, सकारात्मक आय देने वाली परिसंपत्तियों में निवेश और सतत निगरानी। इन सिद्धांतों के साथ आप संभवत: 50 साल या

उससे पहले सेवानिवृत्ति ले सकते हैं।

क्रेडिट: विकास की प्रेरक शक्ति

बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो क्रेडिट फायदेमंद हो सकता है। आप अपनी बढ़ने वाली परिसंपत्ति की खरीद के लिए क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं जो आपको दीर्घकाल में समृद्ध बनाने में मदद कर सकती है व आपको और अधिक वित्तीय रुप से स्वतंत्र बना सकती है। आपात स्थिति में क्रेडिट आपको लिक्विडिटी उपलब्ध करा सकती है बनिस्बत इसके कि आप लंबी अवधि की बचत योजनाओं में जमा पैसे समय पूर्व निकालें और ब्याज का नुकसान उठाएं।

आपकी जरुरतों व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ऋणों में अनेक विकल्प मौजूद हैं जैसा होम लोन, कन्ज्यूमर ड्यूरेबल लोन या पर्सनल लोन।

मीडिया में प्रकाशित एक सर्वे के मुताबिक भारत में पर्सनल लोन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 46 फीसदी की वृद्धि हुयी है और 67 फीसदी ऋण प्राप्तकर्ताओं ने अपने जीवन में किसी न किसी समय फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन लिया है।

यहां तक कि होम क्रेडिट की वार्षिक स्टडी- हाउ इंडिया बारोज (एचआईबी) 2022, एक ऋण प्राप्तकर्त्ताओं की शापिंग या ऋण लेने में ईएमआई कार्ड की पसंद को दर्शाती है और महामारी के उपरांत ग्राहक बड़ी खरीद को आसान ईएमआई के जरिए करने में रुचि दिखा रहे हैं।

निवेश – अपने पैसों अपने काम आने लायक बनाएं

सेवानिवृत्ति कार्पस बनाने को आतुर लोगों को लिए निवेश के कई विकल्प हैं। यदि आप अधिक जोखिम भरे रास्ते को अपना कर अधिक ग्रोथ चाहते हैं तो आपके लिए शेयर बाजार में निवेश एक विकल्प है। आप आईपीओ के जरिए सीधे शेयरों में निवेश करते हैं या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्युचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं।

रियल एस्टेट भी निवेश का एक विकल्प है जहां आप बिना सक्रिय रुप से काम किए आय पैदा करते हैं। किराए पर दी जाने वाली संपत्तियां आय का एक सतत जरिया बनती हैं जिनमें समय के साथ वृद्धि भी होती है।

इसके अलावा निवेश के अन्य तरीकों में वो हैं जो सेवानिवृत्ति होने तक दीर्घकाल में न्यूनतम जोखिम के साथ बराबर रिटर्न देते हैं इनमें शामिल है एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड (ईपीएफ), लंबी अवधि (पांच साल या ज्यादा) की सावधि जमा योजनाएं, सर्राफा, सरकारी योजनाएं जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ), कर मुक्त डाकखाने की योजनाएं, सरकारी प्रतिभूतियां और नैशनल पेंशन स्कीम।

निवेश की योजना बनाते समय यह आवश्यक है बहुआयामी विकल्पों का चयन किया जाए और समूचा निवेश एक ही जगह न किया जाए। यह जोखिम की भरपाई में मदद करता है और परिसंपत्तियों से बढ़िया रिटर्न दिलाने में मदद करता है।

एक वित्तीय सलाहकार के चयन में क्या ध्यान में रखे?

अपने समय पूर्व सेवानिवृत्ति की योजना बनाने के लिए वित्तीय सलाहकार की सेवा लेते समय उसकी शिक्षा व अनुभव, शुल्क का ढांचा, निवेश का दर्शन और जोखिम प्रबंधन की अप्रोच को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार वह है जो खास आपके लिए वैयक्तिक सेवानिवृत्ति योजना बना सके व आपके अनूठे लक्ष्यों, जोखिम सहने की क्षमता और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखे और आपकों अपने सेवानिवृत्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सतत सहयोग व निर्देशन उपलब्ध कराता रहे।

आज के व्यस्त जीवन व इस दुनिया में आप अपने शौक के लिए या जो करना चाहते हों उसके लिए समय भले न निकाल सकें लेकिन सही आयु पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति आपको अपना इच्छित करने का उपहार दे सकती है। ●●●

कविता

मैं नदी हूं

देशव्यापी वर्मा

मैं नदी हूं, मैं उद्गामिनी हूं,
मुझे मत रोको,मुझे बहने दो।।
मुझे कोख मिली हिमानी की
जन्मते ही हो गई वेगवती।
उत्तुंग शिखर, पाषाण विशाल,
बह निकली सबको चीरती।
किसने देखा, इस क्रम में मिले
कई आघातों-प्रतिघातों को।
पर बढ़ते चलने के निमित्त,
मुझे सहने दो, बस सहने दो।
मैं नदी हूं, मैं उद्धारित हूं,
मुझे मत रोको, मुझे बहने दो।।
जब मिली धरा समतल-समतल,
मेरी गति हुई मन्थर-मन्थर।
जल का जब रज से हुआ मिलन,
फूटे कितने अंकुर तन-मन।
अम्बार लगे धन-धान्यों के,
खिले इंद्रधनुष कई रंगों के।
सबके आनन्द में आनन्दित,
स्वयं दूर रही वरदानों से।
मुझे कहने दो, बस कहने दो,
मैं नदी हूं, मैं अवतारित हूं।
मुझे मत रोको, मुझे बहने दो।।
भावनाओं की अतिवृष्टि से,
अकुलाई और क्रोधित होकर।
जब तोड़ चली तटबन्धों को,
तब हाहाकारी रोर मचा।
कई आरोपण-प्रत्यारोपण,
फिर बांधे गए तटबन्ध कई।
ऊर्जा के कितने स्रोत मिले,
जन-जीवन हुआ प्रकाशमयी।
पर अंतिम लक्ष्य अभी पाना है,
सागर से मिलने जाना है।
अब रहने दो,बस रहने दो,
मैं नदी हूं, मैं उद्वेलित हूं।
मुझे मत रोको, मुझे बहने दो।

एक गिरह ऐसी भी

कुमकुम श्रीवास्तव
लखनऊ

बे...बी... बे...बी! बेस बाल खेलने चलोगी ? नीचे से एक तेरह चौदह साल की लड़की आवाज़ें लगा रही थी। तभी ऊपर छत पर आवाज के साथ एक सांवला सा चेहरा चमका, 'न..हीं! अम्मी पढ़ा रही हैं।' उसी वक्त अम्मी ने छत से ही आवाज लगाई, 'आओ, ऊपर आ जाओ सुमन, बढ़िया नाश्ता तैयार है।' अब तो सुमन के मुंह में नाश्ते के नाम पर पानी आ गया, क्योंकि अम्मी बहुत बढ़िया लज़्ज़तदार, मज़ेदार-मज़ेदार चीज़ें बनाकर रखती थीं। बेबी उनकी इक़लौती लड़की थी, नाम था फरज़ाना। जिस किसी भी चीज़ को वह हाथ लगाती थी, उसकी अम्मी अब्बू उसे खरीद देते थे।

आज ना जाने क्यों सुबह से ये खुशनुमा दृश्य सिनेमा की तरह ज़ेहन में बार बार आये जा रहे थे। फ़रज़ाना और सुमन पक्की सहेलियां थीं। दोनों के घरों में भी बहुत दोस्ताना था। सच्चाई से रुबरु कराती इसकी दास्तान ऐसी रही कि वह अर्श से फ़र्श पर आ गई। किसी समय वह अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती थी। दो भाइयों की लाड़ली बहन थी। सबसे छोटी होने की वजह से शैतान भी थी, ज़िद्दी भी कम नहीं थी। इतने में भागते हुए सुमन ऊपर उनके घर पहुंच गई। पहले तो अम्मी ने बेबी के साथ थोड़ा पढ़ाया और खाने के लिए दही की फुलकी, साथ में हलुवा पराठा भी दिया, और बहुत इसरार के साथ खाने की ज़िद करने लगीं। वह तो खाने के लिए ही गई थी। पढ़ने के लिए थोड़े ही गई थी। बड़ा ही गज़ब स्वाद था अम्मी के हाथों में और वह बेबी! वह तो खाने में बहुत नख़रे करती थी। बहुत बहला फुसला कर उसको खिलाया पिलाया जाता था। हालांकि थी भी बहुत ज़हीन। अपने दरजे में अव्वल आती थी, और मॉनिटर भी थी। देखने सुनने में तो वह औसत लड़की थी, लेकिन अपने हंसमुख किरदार की वजह से वह सब की चहीती बनी हुई थी। एक से एक बढ़कर तमाम तरह के उसके पास जोड़े थे। जब उसके यहां जाते थे वह अपना भानमती का पिटारा लेकर बैठ जाती थी। यह देखो, यह वाला जोड़ा बड़ी ख़ालू ने दिया है, या फिर यह नाखूनी चचाजात भाई दुबई से लाए थे। यह बुंदे, वह चूड़ी, लाल रिबन, वगैरा-वगैरा। तमाम बातें, तमाम चीज़ें,और तमाम तामझाम। एक से एक अफ़लातूनी किस्से वह अपनी ज़ुबानी सुनाती थी। कोई भी महफ़िल उसके बग़ैर नहीं हो सकती थी। सिनेमा उससे छूटता नहीं था। स्कूल में हर रोज़ अपनी जेब खर्च से बुआ से कड़ुवे चने खरीदती थी। लड़कियों के स्कूलों में उस समय चटर पटर और चूरन चाट बेचने के लिए महिलाएं ही होती थीं, उन्हीं को बुआ कहा जाता था। बहुत देर में ये बात भेजें में बाबस्ता हुई थी।

सभी दोस्तों को खूब खिलाती पिलाती थी। बहुत बड़े दिल वाली और नेक तबियत थी उसकी। एक बार किसी शादी में शहर से बाहर जाना था। सुमन के

पास कीमती कपड़े नहीं थे। लिहाजा उसने फरज़ाना से कुछ जोड़े उधारी में मांग लिए और उसने खुशी-खुशी दे भी दिए। रिश्तेदारी में धाक जमा के आई थी सुमन, सालों साल उसके पहने कपड़ों के बारे में बातें होती रहीं।

कॉलेज में हफ्ते में एक दिन कहकशां नाम का पीरियड होता था उसमें सभी लड़कियों को अपना-अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता था। मसलन, गजलें, नज़्म कहानी, अंताक्षरी आदि। जिसको जो भी आता था, वह सब को सुनाता था। बढ़िया होने पर ईनाम इक़राम से भी नवाज़ा जाता था। फरज़ाना के पास ढेरों ईनाम थे। उसको नज़्म लिखने का बहुत शौक़ था। आर्ट और क्राफ्ट में भी महारत हासिल थी। उर्दू साहित्य में उसने प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पीएचडी की हुई थी। उसकी थीसिस टॉप पर थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री साहब द्वारा गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ था।

उसके अब्बू के पास उनके नाम से मकान के अलावा इसी शहर में एक खाली जमीन भी थी। जिस पर उसने सुमन के साथ मिलकर बहुत मेहनत मशक्कत से एक स्कूल बनाया था। घर घर जाकर परचे बांटे थे, आज की तवारीख में नामी गिरामी स्कूलों में उसका शुमार होता था। एक ख़ास बात और, वो ये कि उसके गले में बेहद मिठास भरी हुई थी। स्कूल के सालाना जलसे से लेकर मिलाद, नातें, यहां तक कि फ़ातिहा पढ़ने के लिए भी उसको बुलाया जाता था। अपनी मेहनत के बल पर उसने समाज में एक बेहतरीन मुक़ाम हासिल कर लिया था। अक्सर उसकी किस्मत पर रश्क़ भी होता था।

जब भी फ़रजाना से मिलते थे उसकी इश्कबाज़ी का एक नया शिगूफ़ा सुनने को मिलता था। बक़ौल बेबी हर रोज़ उसके लिए एक नया शादी का पैग़ाम आया रहता था, सब लड़के उस पर मर मिटने के लिए तैयार रहते थे, बस इसकी हां कहने की देर होती थी। कइयों की तो सुमन भी गवाह थी। हालांकि इनके लटके झटकों से बेहद आज़िज आ चुकी थी। फ़ैशन की दीवानी बेबी लैक्टो कलामाइन की संगत से अपनी आबनूसी रंगत को निखारने में जुटी रहती थी। वजन थोड़ा अब बढ़ने लग गया था, इसलिए डाइटिंग के चक्कर में खाने को हाथ भी नहीं लगाती थी। रोज़ाना उसके ख़याली पुलाव पकते रहते थे। लेकिन सारी किस्से कहानियां बेबुनियाद साबित हुईं। वही ढाक के तीन पात वाली कहावत सच हो गई। कहते हैं कि शादी ब्याह सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर उसने जोड़ी बनाई है तो कोई रोक नहीं पायेगा, लेकिन अग़र किस्मत में ही किसी का साथ नहीं है तो लाख कोशिशों के बाद भी बात बनती नहीं है। बस छांटने बीनने में उसका वक्त ज़ाया हो गया। उसे कोई अपने जैसा मिला ही नहीं।

समय का पहिया तेजी से भाग रहा था। सुमन भी अपनी गृहस्थी में रम गई थी। उसके ख़ाविंद की नौकरी दूसरे शहर में थी इसलिए अब फ़रजाना से ताल्लुकात लगभग ख़त्म से थे। कोई ख़त-ओ-किताबत भी नहीं थी, उस समय मोबाइल का जमाना भी नहीं था। लगभग तीस साल गुज़र गये।

सुमन के पति भी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे इसलिए वह वापस अपने शहर में रहने आ गई। रह रह कर उसके ज़ेहन में फ़रजाना का अक्स तैरता रहता था। सोशल मीडिया पर भी उसने ढूंढने की बहुत शिद्दत से कोशिश की लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दिल बहुत ज़्यादा जब बेचैन हो गया तब वह अपने शौहर के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गई। ढूंढते ढूंढते जहां दोनों सहेलियों का ख़ूबसूरत बचपन गुज़रा था, वहां पहुंच गई। लेकिन वहां के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सारी नई इमारतें थीं, कुछ भी पुराना सा नहीं लग रहा था। सब नये चेहरे थे, कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था। बेस बाल मैदान पर नये मकान बन गये थे। वहीं पास में कुछ बच्चे खेल रहे थे। कुछ ख़ातूने क्रोशिया और कढ़ाई के काम में मशगूल थीं। एक लड़की ड्योढ़ी पर बैठकर दूसरी लड़की के सिर के जुओं के आराम में ख़लल डाल रही थी। लग रहा था कि सुमन रास्ता भूल गई है। घर ढूंढते हुए उसके पति की सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। अब वह चिड़ चिड़ करने लगे थे, कायदे से वह थक चुके थे, उन्हें कोई दिली मोहब्बत तो थी नहीं, वह तो सील

मुलाहिज़ा में आ गए थे। कुछ भूख का भी एहसास हो रहा था। सुमन की आंखों से मुस्तकिल गंगा जमुना बह रही थी। कोई ज़रिया नहीं था जिससे वह अपनी सहेली को ढूंढ पाती। लेकिन उसने हिम्मत बरक़रार रखते हुए किसी से पूछा, 'ये डॉ फ़रजाना फ़ातिमा कहां रहती हैं?' 'इस नाम से यहां कोई नहीं रहता है।' जवाब मिला। सुन कर इन्तिहाई अफसोस हुआ। लेकिन कहते हैं ना किसी को शिद्दत से ढूंढने पर पूरी कायनात उसे मिलाने पर आमादा हो जाती है, यही सुमन के साथ हुआ। वह वापसी के लिए मुड़ी ही थी कि एक दस बारह साल का लड़का दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए पूछने लगा, 'कहीं आप बेबी आपा को तो नहीं ढूंढ रहीं हैं?' सुमन ने बौखलाहट में रुंधे गले से कहा,'हां..हां वही।' लड़का कहने लगा, 'यहां उन्हें फ़रजाना नाम से कोई नहीं जानता, आइये आपको उनके घर ले चलते हैं।' बेचारी सुमन उसके पीछे-पीछे चलने लगी, उसे यह भी होश नहीं था कि उसके पति साथ में आ भी रहे हैं या नहीं। थोड़ा सा आगे जाने पर वह एक खंडहरनुमा मकान के आगे जाकर रुक गया, इशारे से बता दिया कि यही घर है और पलट कर भाग गया।

कई बार कुंडी खटखटाने के बाद चरमराते हुए दरवाज़ा खुला, सामने मैले कुचैले कपड़े पहने अदब से सिर ढंके हुए डा फ़रजाना खड़ीं थीं। उसको देख कर सुमन की रुह फ़ना हो गई। क्या ये वही थी जो हमारे दिलो दिमाग में बसी थी? नहीं! ये इतराती हुई, इत्र महकाती हुई, चटखारों के साथ किस्से कहानियां सुनाती हुई फ़रजाना नहीं थीं। ये तो किस्मत की मारी एक ख़ातून थीं।

अन्दर जैसे ही कदम रखा एक बदबूदार भभका सुमन की नाक में समा गया, उबकाई आते आते बची। चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो दिल हलक़ में आ गया। हर तरफ ग़ुरबत पसरी थी, एक ख़ौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। सुमन के दिल ने ऐसा लग रहा था कि धड़कना बन्द कर दिया था। किसी समय ये घर गुलज़ार हुआ करता था। जल्दी से उसने दरवाजे से किसी बच्चे से दस रुपए के बिस्कुट मंगवाये मेहमाननवाज़ी के लिए। बेहद गंदे कांच के गिलास में पानी पीने के लिये दिया। ये सब देख कर कलेजा फट सा गया।

सुमन की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कैसे उसका हालचाल पूछे। पहले तो दोनों सहेलियां फूट फूटकर जी भर रोईं, जब ग़ुबार कुछ हल्का हुआ तो उसने बताना शुरू किया कि कैसे मीनमेख निकालते धीरे-धीरे उम्र गुज़रती गई। कुछ साल पहले एक दुहाजू तीन बच्चों के बाप से किसी ने रिश्ता लगवाया था, वह तैयार भी हो गई थी। लेकिन इसकी भावज ने भांजी मार ली और रिश्ता ख़त्म करवा दिया। इस बीच वालदैन ने भी ऊपर का रुख़ कर लिया था। भाइयों ने कन्नी काटने के साथ स्कूल पर भी कब्ज़ा कर लिया। इसके हाथ कुछ नहीं लगा। कहने को तो सब कोई था लेकिन 'सफ़र ए ज़िन्दगी में जब कोई मुश्किल मक़ाम आया, ना ग़ैरों ने तवज्जो दी, ना अपना कोई काम आया।' सच है वक़्त बदलते और दिमाग़ फ़िरते देर थोड़े ही लगती है।

जिस घर में यह अपने मां बाप के साथ ख़ुशनुमा ज़िन्दगी बिताती थी। उसी घर के एक कोने में ये पड़ी थीं। घर पूरा सांय सांय कर रहा था और ढहने के कगार पर था। सारे कमरे ढह चुके थे। टीन के अंगड़ खंगड़ जैसी गृहस्थी रखी थी। टूटा हुआ तख़्त जिस पर हद से गंदा बिछौना बिछा था, उस पर वह लेटी हुई थी। पहले की जानकारी के अनुसार उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। दरियाफ़्त करने पर पता चला की उसके भाई भावज ने उससे मकान खाली करवाने एवं स्कूल से बेदख़ल करने के लिए एड़ी चोटी का पुरज़ोर जोर लगा दिया था। अब्बू इसको भी स्कूल और घर दोनों में वारिस बना गये थे। यही कलह की जड़ था। उसको मरवाने तक की साज़िशें रची गईं थीं। लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ये बात दुनिया जानती है। इस बीच इसके बड़े भाईजान का भी इंतक़ाल हो चुका था। यह भी कुछ कम नहीं थीं। इन्होंने भी कचहरी मुक़दमा करके, अपनी ज़िन्दगी ग़ारत कर दी। जो गृहस्थी सामने रखी थी, कबाड़ी वाला उसके बदले नमक भी ना दे। टूटे फ़ूटे टीन के कुछ डिब्बा डिब्बी रखे थे। एक जंग लगी गैस प्लेट रखी थी। बाबा आदम के जमाने का ब्लैक एण्ड व्हाईट टी वी रखा था। इत्तफ़ाकन वो चल भी रहा था। इसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी। लंगड़ा कर चल रही थी। महीनों सरकारी अस्पताल में भर्ती भी रही थी। कोई पुरसाहाल नहीं था। एक निवाला, एक गिलास पानी भी कोई पूछने वाला नहीं था। पैसे पैसे की मोहताज़ थी। सारी जमा पूंजी वकीलों की भेंट चढ़ चुकी थी। रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था, कि क्या पता कब ये कुछ मांग बैठे। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। काफ़ी बातचीत के बाद सुमन बोली, 'यह सब छोड़ो, अब किसी का हाथ थाम लो, जिससे तुम्हारे बचे खुचे कुछ दिन तो आराम से गुज़र सकें।' वह बोली, 'ऊपर वाला चाहेगा तो हम जरूर जीतेंगे और यह मकान हासिल करके रहेंगे। सारा डूबा हुआ पैसा छोटे भाईजान वापस करेंगे।' जल्दी जल्दी वह एक पुरानी टीन की बकसिया से दुनिया भर के मकान के खस्ताहाल दस्तावेज निकाल कर दिखाने लगी। मन में सोचा कि, 'हासिल भी कर लोगी तो ज़िंदगी कितने दिन की बची है।' सुमन ने बहुत समझाने की नाक़ाम कोशिश की, यह भी कहा कि 'तुम क्या थीं और क्या हो गईं।' उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि,'शौक ही नहीं रहा कि अब किसी को साबित करूं, अब तो जो आप समझ लें वही हूं मैं।' पूरी ज़िंदगी ज़मीन के एक टुकड़े के पीछे उसने तबाह कर ली। हासिल कुछ ना कर पाई, ना ख़ुद वह,ना ही उसके भाई भतीजे खुश रह पाये। सारी ज़िन्दगी एक दूसरे की ख़िलाफत में काट दी। क्या फ़ायदा हुआ इससे? यही किसिम किसिम की गिरहें होती हैं जिनसे लोग ताउम्र निकल नहीं पाते हैं, कीमती ज़िंदगी को यूं ही हवा में उड़ा देते हैं। ●●●

भैंस की तलाश

अरुण गुप्ता

जिसने सुना,वही भौंचक रह गया। खबर ही ऐसी थी। जिले के बड़े साहब की भैंस रातोंरात सरकारी कोठी से लापता हो गयी। सुबह-सुबह नाज़िर सदर कलेक्ट्रेट की सफाई की देख रेख, तहसीलदार अपनी बेड टी और कोतवाल बिस्तर छोड़ कर सीधे कलेक्टर की कोठी पर हाजिर।

वाकया कुल इतना कि कोठी के पिछवाड़े बंधी साहब की ससुराल से मिली मुर्रा भैंस आधी रात के बाद खूंटा पगहा समेत खुले फाटक और ऊंघते संतरी का लाभ उठा कर आराम से टहलती हुई बाहर चली गई। कलेक्टर साहब तो संजीदा थे ही, मेम सा'ब पर तो मानो दुख का पहाड़ ही टूट पड़ा हो।खबर पा कर पुलिस कप्तान, सीएमओ और दीगर आला अधिकारी भी मिजाज़पुर्सी को पंहुचे। कोठी की सुरक्षा में तैनात पूरी सशस्त्र गार्द के जवान और तीन चपरासी निलंबित कर दिए गए। कोतवाल और तहसीलदार ने अपने अपने मातहतों को गुमशुदा की तलाश में जुट जाने का हुक्म देते हुए वाकये की किसी को कानोकान खबर न होने देने की भी ताकीद की, खासकर जिले के पत्रकारों को। अब शहर की सारी पुलिस,लेखपाल और नगरपालिका के मुलाजिम साहब की भैंस की तलाश में मामूर कर दिए गए। बाकी सभी सरकारी कामकाज मुल्तवी कर दिए गए। बहरहाल, पूरा दिन, पूरी रात के बाद अगला दिन भी गुजर गया। पूरी मुस्तैदी, सारी हिकमत अमली के बावजूद गुमशुदा भैंस का अता-पता भी न मिल सका। कुछ अफसरों को यह भी शुबहा रहा कि भैंस की तलाश के बजाय कर्मचारी अपने निजी घरेलू कामों को निपटाने में मसरुफ हैं। तलाश बदस्तूर जारी थी। सरे शाम वह हो गया जिसे रोकने के लिए सख्त ताकीद की गई थी। शाम को कचहरी के पास सड़क किनारे बने दुलारे के चाय के छप्पर में पड़ी बेंच पर कलेक्टर की कोठी से निलंबित गार्द के दो सिपाही चाय की चुस्कियों के बीच अपने भाग्य को कोस रहे थे। वहीं दूसरी बेंच पर दैनिक विश्व वार्ता के जिला ब्यूरो प्रमुख आशू जी भी चाय के घूंट के साथ सिगरेट के कश लगा रहे थे, के

कान तक सिपाहियों की बातचीत के कुछ शब्द पंहुच ही गये। एक एक अतिरिक्त चाय के बदले उन्हें अगली सुबह के अखबार के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुकी थी।

अगले दिन अखबार में भैंस के लापता होने की खबर पढ़ शहर के बाहरी इलाके में बने तबेले के मालिक बल्लू घोसी ने पास की पुलिस चौकी पर जाकर दारोगा जी को इत्तिला दी कि दो दिन पहले लावारिस घूम रही एक भैंस को अपने तबेले में पनाह दी थी। आज अखबार में बड़े साहब की खबर पढ़कर भागकर आपको बताने आया हूं। दारोगा जी ने फौरन कोतवाल सा'ब को वायरलेस पर इत्तिला की और कोतवाल तुरत-फुरत जीप लेकर साहब की कोठी की तरफ भागे और आनन फानन में वहां से भैंस की शिनाख्त के लिए दो कारिंदों को साथ लेकर बल्लू के तबेले पर लगभग दबिश के अंदाज में धावा बोल दिया। कारिंदों के भैंस की शिनाख्त करते ही कोतवाल अपने रंग में आ गए। बेचारे बल्लू को अर्दब में लेते हुए गुर्राए-"ससुरे,जिले के हाकिम की भैंस दाब कर बैठ गया। परसों ही इत्तिला क्यों नहीं की? मारे मारे घूम रहे हैं तीन दिन से। पांच हजार का तेल फुंक गया गाड़ियों में।" कोतवाल सा'ब के हुड़दंग के बीच बल्लू ने तबेले के सभी कारिंदों को लगाकर साहब की भैंस को नहला धुला कर, तेल लगा कर चमका दिया। नयी रस्सी का पगहा भी गले में बांध दिया गया। कहीं से गुलाबी रंग का रिबन मंगा कर भैंस को सजा भी दिया गया। चलते समय बल्लू ने कोतवाल सा'ब को भीतर ले जाकर चुपचाप उनके पेट्रोल खर्च की भरपाई भी कर दी।आखिर तबेला भी तो चलाना था। अब कोतवाल सा'ब भैंस का पगहा खुद अपने हाथ में थाम कर पैदल ही एक छोटे मोटे जुलूस की अगुवाई करते साहब की कोठी पर पंहुच कर सलाम ठोका और साहब से शाबासी और उनकी मेम सा'ब से बतौर ईनाम पूरे एक हजार का नोट हासिल किया। गुमशुदा भैंस की तलाश पूरी हुई और इस काम में तैनात सरकारी मुलाजिमों को अपने अपने सरकारी काम पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ●●●

दो दिनों का मेहमान

वर्षा पटेल,
ब्रुकलिन स्कूल देहरादून

एक दिन मेरे पिताजी एक कछुए को घर ले आए। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, कि उनके किसी मित्र ने यह कछुआ उनको दिया है क्योंकि, उनको अपने माता-पिता से मिलने बहुत दूर जाना है और वह दो दिन बाद लौटने वाले हैं। जब वह वापस लौटेंगे ,तो हम यह कछुआ उनको वापस लौटा देंगे। तब तक हम इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे। मैं बहुत खुश थी क्योंकि वह कछुआ बहुत प्यार था। मैंने उसका नाम रखा टॉमी। मैं शाम के समय अपने पिताजी से पूछा कि क्या हम टॉमी को लेकर पार्क जा सकते हैं? उन्होंने मुझे अनुमति दे दी। कुछ देर बाद ही हम टॉमी को लेकर पार्क में पहुंचे। उसको देखते ही सब बच्चे उसके पास सलाद के पत्ते लेकर आए और उसे बड़े ही प्यार से खिलाया। तभी एक शरारती बच्चे ने उसके ऊपर बहुत ही तेजी से एक पत्थर फेंका परंतु उसके मजबूत कवच की वजह से उसे चोट नहीं आई। तभी मेरी नजर एक झूले पर पड़ी और मैं उसके पास खेलने चली गई। जब मैं वापस खेल कर लौटी ,तो मैंने देखा कि टॉमी तो वहां पर नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई और इधर-उधर देखने लगी पर तभी मेरी नजर एक बच्चे पर गई जिसने उसे अपने हाथ में बैठा रखा था। मैं बहुत खुश हुई और उसका धन्यवाद किया और फिर हम वापस अपने घर लौट गए।

अगले दिन जब मैं अपने विद्यालय पहुंची, तो मेरी शिक्षिका ने मुझे बताया कि कछुए 100 साल से भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं और उन्होंने मुझे कछुए और खरगोश की एक मजेदार कहानी सुनाई और यह भी बताया कि धीरे चलने वाला और स्थिर रहने वाला हमेशा जीतता है। उस दिन जब मैं घर लौटी तो मैंने देखा कि टॉमी सलाद के पत्ते खा रहा था। शाम को मैं अपने पिताजी के साथ नदी किनारे टॉमी को लेकर गई। नदी किनारे पहुंचते ही, हमने उसके पिंजरे का दरवाजा खोल दिया ताकि वह थोड़ा सा तैर सके। वह तैर कर वापस पिंजरे में आ गया। मैं बहुत दुखी थी कि टॉमी वापस अपने घर हमें छोड़कर जा रहा है पर तभी मेरे पिताजी को उनके मित्र का कॉल आता है। वह कहते हैं कि हम कल नहीं पहुंच पाएंगे इसलिए आप टॉमी को एक और दिन रख लीजिए यह सुनकर मैं बहुत खुश थी। अगले दिन जब मैं अपने विद्यालय से लौटी तो मेरे पिताजी मुझे चिड़ियाघर ले गए जहां मैं विभिन्न प्रकार के जीव जंतु , पशु पक्षी और जंगली जानवर देखी। उसके बाद हम वापस घर लौट गए। घर लौट कर हमने टॉमी की बहुत सारी तस्वीरें खींची ताकि हम उसे हमेशा याद रख सके। जब मैं सुबह उठी तो मैंने टॉमी को अलविदा किया और मेरे पिताजी उसे अपने दोस्त के घर वापस ले गए। मैं बहुत खुश थी कि अब टॉमी हमेशा अपने मलिक के साथ खुशी-खुशी रहेगा।

फागुन मे रंग उड़ा..

गीता खत्री

हुल्लड़ है, होड़ है, एक अलग सा धमाल है..
आया फागुन का महीना, उड़ा रंग पीला लाल है..
बन देवर बाबा घूम रहें है आज सारे मोहल्ले में..
अम्मा भी आज भौजी जैसन मुस्काये लगी है पल्ले में..
रंग भरी बाल्टी को लेकर होड़ है, उछाल है...
आया फागुन का महीना, उड़ा रंग पीला लाल है..
भंग का गिलास आज जो फूफा गटक गए..
लेकर कनस्तर भर गुजिया सटक गए..
औंधे गिरे नाली मा हाल भी बेहाल है...
आया फागुन का महीना, उड़ा रंग पीला लाल है...
जीजा का रंग दिया टेसू की धार में.
जिज्जी जाए छिप गई, सखियों की कतार में..
सबके चेहरे भूत बने, बड़ा बुरा हाल है. .
आया फागुन का महीना, उड़ा रंग पीला लाल है...
सारे बैर भाव आज रंगों मे घुल गए...
मन के संताप सब फागुन में धुल गए..
बने सब मित्र मिटा मन का मलाल है,
आया फागुन का महीना, उड़ा रंग पीला लाल है..
आँचल उड़ाती फागुनी बयार चल गई
प्रहलाद भक्त बच गए,होलिका माई जल गई..
विधि का विधान भला कौन सका टाल है..
आया फागुन का महीना, उड़ारंगपीलालालहै

24 घंटे आपातकालीन सुविधा

RBSK
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवायें
अब आपकी पहुँच में...

अमेरिका की स्माईल ट्रेन संस्था द्वारा जन्मजात कटे होंठ एवं कटे तालू का नि:शुल्क ऑपरेशन एवं उपचार

अमेरिका की स्माईल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी सम्बद्ध

हेल्थ सिटी हास्पिटल
TRAUMA CENTRE & SUPERSPECIALITY HOSPITAL
गोमती नगर थाने के पीछे

पहले

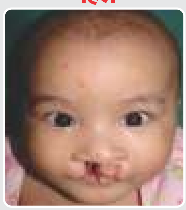

SmileTrain
TEAM EMPOWER

बाद में

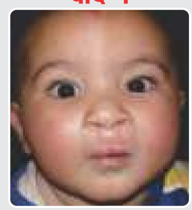

डॉ0 आदर्श कुमार
सीनियर कन्सल्टेंट–स्माइल ट्रेन,
प्लास्टिक सर्जन

डॉ0 रोमेश कोहली
प्लास्टिक सर्जन

डॉ0 एस.पी.एस. तुलसी
मैक्सिलोफेशियल सर्जन

डॉ0 वैभव खन्ना
प्रोजेक्ट डायरेक्टर–स्माइल ट्रेन,
प्लास्टिक सर्जन

प्लास्टिक सर्जरी विभाग में उपलब्ध अन्य सुविधायें

- समस्त प्रकार की चोट, यातायात दुर्घटना एवं घायल अवस्था (All types of Trauma & Accidents)
- जन्मजात एवं अन्य विकृतियों की पुन: निर्माण शल्य क्रियायें (Reconstructive Surgery)
- रीप्लान्टेशन व माइक्रोवैस्कुलर शल्य क्रिया (Replantation & Microvascular Surgery)
- कॉस्मेटिक शल्य क्रियायें (Cosmetic Surgery)
- बाल प्रत्यारोपण (Hair Transplant)
- अन्य समस्त प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है

अगर आप ऐसे किसी भी रोगी को जानते हैं तो तुरन्त निम्न पते पर भेजें या सम्पर्क करें:

SmileTrain
Changing the World One Smile at a Time

SMILE TRAIN PROJECT (U.S.A.)-
FREE TREATMENT OF CLEFT LIP AND CLEFT PLATE PATIENTS

NH-A & B Vijay Khand-2, Gomti Nagar, Lucknow-226010
Ph.: 0522-4063608, 9935880201, 9453167711
Email: dr.vaibhavkhanna@yahoo.in, hrccpllko@gmail.com
www.lucknowwhealthcity.com

HELPLINE
CALL
9454159999

BREAKING NEWS एक्सप्रेस

NEWS AGENCY SINCE 2008

आवश्यकता

- प्रदेश के समस्त **जिला मुख्यालयों/मण्डल** स्तर पर समाचार एजेंसी के लिए **अनुभवी संवाददाताओं** की।
- समाचार एजेंसी के क्षेत्र में कार्यरत पत्रकारों को वरीयता।
- मानदेय व विज्ञापन पर कमीशन की शर्तें लागू।
- समाचार एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए हमारी वेबसाइट **www.breakingnewsexpress.com** पर विजिट कर सदस्य बनें।
- **लखनऊ जंक्शन** (राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक) व **लखनऊ जंक्शन (मासिक पत्रिका)** से जुड़ने के लिए हमें ईमेल करें। Email-lkojunction@gmail.com

विशेष

बी.एन.ई. मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड-पीआर एजेंसी, विज्ञापन, ऑनलाइन मीडिया, वेब पोर्टल के अलावा सरकारी/कारपोरेट सेक्टर से जुड़े विभागों के समाचार प्रबंधन व जन सम्पर्क अभियान में भी अपनी सहभागिता देने के लिए आप तक पहुंचने के लिए इच्छुक है।

B.N.E. Media Network (Pvt) Ltd,

एम.आई.जी.-47 सेक्टर ई, अलीगंज, लखनऊ (यूपी)

फोन: 0522-4232552, मो. 7376547600, Email.breakingnewsexpress@gmail.com